

शासकीय लोचन प्रसाद पाण्डेय कॉलेज में वीर गाथा और सैन्य समारोह आयोजित

सारंगढ़। सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिवस आज शासकीय लोचन प्रसाद महाविद्यालय सारंगढ़ में आयोजित वीर गाथा और सैन्य सम्मान समारोह में देश के वीर अमर शहीदों ,सेवानिवृत्त फौजी भाइयों पुलिस जवानों को उनके उल्लेखनीय योगदानों के लिए भावभीनी श्रद्धांजलि और भावपूर्ण नमन किया गया।इस विशेष अवसर पर मुख्य आतिथ्य के रूप जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय उपस्थित रहे।कार्यक्रम में देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले वीर जवानों ,पूर्व सैनिकों और रा़र रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की अद्वितीय योगदान को याद कर उन्हें नमन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने अपने समसामयिक और ओजस्वी उद्बोधन से उपस्थित युवाओं मे रा़र प्रेम की नई अलख जगाई। जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने अपने उद्बोधन में अमर शहीदों को नमन और सैन्य बलों का आधार जताते हुए कहा कि आज हम जिस आज़ाद और सुरक्षित वातावरण में सांस ले रहे हैं वह देश के उन वीर जवानों की बदौलत है जो माइनस डिग्री तापमान से लेकर तपती रेगिस्तान तक की सीमा पर मुस्तैद रहकर अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। हमारी आने



वाली पीढ़ियों को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारी आज की शांति उन वीरों की कल की त्याग और बलिदान की नींव पर टिकी हैं। उन्होंने सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के उन वीर माटी पुत्रों के योगदान को विशेष रूप से रेखांकित किया,जिन्होंने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी।उनके परिवारों के परिजनों को भी नमन किया।

जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने देश के भावी पीढ़ी जेन जी को रा़र के समग्र विकास में सकारात्मक बदलाव लाने भूमिका सुनिश्चित करने हेतु आग्रह करते हुए कहा कि हमारी नई पीढ़ी जेन जी के पास नई नई तकनीक,नवाचार और असीमित ऊर्जा का भंडार है।उन्होंने विकसित भारत के सपनों और संकल्पों को साकार करने में अग्रणी भूमिका निभाने

के लिए आह्वान किया।जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय ने युवा पीढ़ी से आग्रह किया कि वे नकारात्मक सोच और विचार को त्याग कर विकसित भारत के अपनी तमाम ऊर्जा को देश के नाम समर्पित करें। उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी अनुशासन, समयबद्धता समर्पण और देश भक्ति और कठिन परिश्रम को अपना मार्गदर्शन बनाए और किसी भी परिस्थितियों में रा़र के मान सम्मान को सर्वोपरि रखे। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष संजय भूषण पाण्डेय,जिला पुलिस कप्तान सुनील शर्मा,जिला पंचायत के सीईओ ऋषिकेश तिवारी, सेवानिवृत्त सैनिकगण,पुलिस के अन्य अधिकारी प्राचार्य डॉ लोकेश्वर पटेल, प्राध्यापकगण और भारी संख्या में एनसीसी और विद्यार्थी उपस्थित रहें।

खुशहाल जिंदगी का नया पताड प्रधानमंत्री आवास योजना ने खिरमनी के सपनों को दी नई पहचान

जगदलपुर। कच्चे छप्पर से टपकती बारिश की बूंदें, मिट्टी का गीला फर्श और अनिश्चितता का साया बस्तर जिले के जनपद पंचायत जगदलपुर अंतर्गत ग्राम पंचायत कुरंदा की रहने वाली 45 वर्षीय खिरमनी की जिंदगी बीते दो दशकों से इन्हीं मुश्किलों के बीच गुजर रही थी।

करीब बीस वर्ष पहले पति के छोड़ जाने के बाद खिरमनी के सामने अपनी नन्हीं बेटी के पालन-पोषण की बहुत बड़ी चुनौती थी, जिसके लिए उन्होंने मजदूरी का रास्ता चुना और एक जर्जर झोपड़िनुमा घर में अपनी बेटी के साथ दिन गुजारने लगीं। हर साल बरसात और चिलचिलाती धूप में इस मां-बेटी के सामने सिर छिपाने की गंभीर समस्या खड़ी हो जाती थी, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) ने उनके इस दो दशक लंबे संघर्ष को समाप्त कर एक सुरक्षित और पक्के आशियाने का सपना साकार कर दिया है।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में स्वीकृत हुए इस पक्के मकान के लिए शासन द्वारा खिरमनी को कुल एक लाख 20 हजार रुपये की सहायता राशि तीन किश्तों में सीधे उनके



खाते में प्रदान की गई, जिसमें पहली किश्त 40 हजार, दूसरी किश्त 60 हजार और तीसरी किश्त 20 हजार रुपये की थी। 27 वर्गमीटर में बनने वाले इस दो कमरों और रसोईघर वाले मकान की कुल निर्माण लागत एक लाख 45 हजार रुपये आई, जिसके अतिरिक्त खर्च की व्यवस्था के लिए खिरमनी ने कहीं हाथ फैलाने के बजाय स्वयं अपने घर के निर्माण में मजदूरी का काम किया और महात्मा गांधी नरंगा के माध्यम

से उन्हें 90 दिनों का मजदूरी भुगतान प्राप्त हुआ। निर्माण कार्य के दौरान जनपद पंचायत स्तर के तकनीकी सहायक, विकासखंड समन्वयक और ग्राम पंचायत सचिव का भरपूर सहयोग मिला तथा न्यूनतम दरों पर निर्माण सामग्री सुलभ होने से बिना किसी अड़चन के यह घर तेजी से बनकर तैयार हो गया।

अब नए और पक्के घर की चौखट पर खड़ी खिरमनी अपनी पुरानी तकलीफों को पीछे छोड़

सुकून की सांस ले रही हैं। वे भावुक होकर बताती हैं कि यह सिर्फ ईंट और गारे की इमारत नहीं, बल्कि उनके कच्चे घर से पक्के आशियाने तक के गौरवशाली बदलाव की कहानी है, जिसने उन्हें न केवल धूप और बारिश से स्थायी सुरक्षा दी है बल्कि सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जीने का नया सहारा भी दिया है। अपने इस नए आशियाने के लिए वे दिल से शासन-प्रशासन का आभार प्रकट करती हैं।

तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी निलंबित

कवर्धा। लापरवाही के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम करते हुए साय सरकार ने तहसीलदार को निलंबित कर दिया। निलंबित तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी पर आरोप है कि उसने कोर्ट के कामों में लापरवाही बरती। शासन की ओर से कराए गए जांच में ये भी ये साफ हो गया कि तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी लापरवाही बरतने के मामले में दोषी हैं।

तहसीलदार के खिलाफ यह कार्रवाई सीएम हेल्पलाइन 1076 पर दर्ज कराई गई शिकायत के बाद हुई। राजस्व विभाग से संबंधित मामलों की समीक्षा के दौरान तहसीलदार के खिलाफ गंभीर लापरवाही बरते जाने की बात सामने आई थी। जिसके बाद निलंबन की कार्रवाई की गई। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, नवा रायपुर अटल नगर से शुक्रवार को निलंबन आदेश जारी किया गया।

शासन की ओर से जारी

सीएम हेल्पलाइन की शिकायत पर सख्त एक्शन



आदेश के अनुसार, तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी कबीरधाम जिले की पिपरिया तहसील में पदस्थ रहे। चंद्रवंशी पर आरोप है कि शिकायतों के निराकरण में गंभीर लापरवाही और स्वेच्छाचरिता उन्होंने बरती, जिसकी शिकायत सीएम हेल्प लाइन पर हुई। प्रकरणों की जांच में तहसीलदार को दोषी पाया गया। जिसके बाद शासन ने उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की।

शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि संबंधित तहसीलदार का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। दरअसल, मुख्यमंत्री विष्णुदेव

साय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीएम हेल्पलाइन में प्राप्त शिकायतों और उनके निराकरण की समीक्षा की गई थी। इस दौरान राजस्व विभाग से संबंधित मामलों में लापरवाही का मुद्दा सामने आया था। इसके बाद संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की गई।

निलंबन अवधि के दौरान प्रमोद कुमार चंद्रवंशी का मुख्यालय जिला कबीरधाम निर्धारित किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भता देय होगा। कार्रवाई के बाद जिले के राजस्व विभाग में सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई की चर्चा तेज हो गई है। प्रशासनिक कामकाज में लापरवाही और शिकायतों के निराकरण में देरी को लेकर शासन की सख्ती से अधिकारी-कर्मचारियों के बीच हड़कंप की स्थिति है।

छत्तीसगढ़

प्रमुख समाचार

2 ठेकेदारों पर जनमन आवास योजना में ठगी के आरोप

कवर्धा। बोड़ला विकासखंड के ग्राम राजाढ़ार और आमानारा का है। यहां आवास निर्माण के नाम पर पैसे लेकर मकान नहीं बनाने के मामले में 2 ठेकेदारों के खिलाफ चिल्की और तरेगांव थाने में एफआईआर दर्ज की गई। 9 हितग्राहियों की शिकायत पर कार्रवाई हुई है। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार, ग्राम राजाढ़ार के 5 हितग्राहियों ने ठेकेदार कुमार मेरावी, निवासी शीतलपानी, पंचायत ढोलकच्चा पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शिकायतकर्ताओं की मांने तो, देवसिंह से 60 हजार, मंभोर बाई से 60 हजार, पुसिया बाई से 60 हजार, कौशल्या बाई से 80 हजार और ननकी बाई से 60 हजार पीएम जनमन आवास निर्माण के नाम पर लिए गए। इसके बावजूद मकानों का निर्माण नहीं कराया गया। करीब डेढ़ साल तक इंतजार करने के बाद भी न रकम वापस मिली और न ही आवास बन पाए, तब पीड़ितों ने इस बात की शिकायत स्थानीय पुलिस से की। 1 लाख 89 हजार लेने की शिकायत पर ठेकेदार तुमसे गोड़ के खिलाफ तरेगांव थाने में मामला दर्ज किया गया है।

धान खरीदी में करोड़ों रुपये का हिसाब नहीं मिला

कबीरधाम। कबीरधाम जिले में धान खरीदी सीजन 2025-26 के आंकड़ों ने व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। उपार्जन केंद्रों से लेकर संग्रहण केंद्रों तक धान के स्टॉक मिलान में करोड़ों रुपये की कमी सामने आई है। विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, उपार्जन केंद्रों में करीब 11 करोड़ 93 लाख रुपए और संग्रहण केंद्रों में लगभग 5 करोड़ 70 लाख रुपये मूल्य के धान का अंतर सामने आया है। दोनों को मिलाकर यह राशि 17 करोड़ 63 लाख रुपये से अधिक है।आठ समितियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बावजूद कमी की पूरी भरपाई नहीं हुई है। अब विभाग संबंधित समितियों के कमीशन से राशि की कटौती कर भरपाई की बात कह रहा है। कबीरधाम जिले के 108 उपार्जन केंद्रों में सीजन के दौरान कुल 6 लाख 37 हजार 235 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई। लेकिन उठाव और स्टॉक मिलान के बाद केवल 6 लाख 33 हजार 392 मीट्रिक टन धान का हिसाब मिल पाया। इस तरह करीब 3 हजार 848 मीट्रिक टन धान की कमी सामने आई।

बस्तर में सायबर ठगी: 2 आरोपी झारखंड से गिरफ्तार

जगदलपुर। बस्तर पुलिस ने सायबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 शान्तिरों को गिरफ्तार किया है। दोनों ही आरोपी झारखंड के जामताड़ा के रहने वाले हैं। दोनों आरोपी लंबे समय से सायबर ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे थे। कई सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार बस्तर पुलिस की टीम ने कोलकाता से इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 82 एटीएम कार्ड 25 हजार नगद और 6 मोबाइल फोन समेत इलेक्ट्रॉनिक सामान बरामद किए गए। बस्तर,स्क्र सुखनंदन राठौर ने कहा, परपा थाना क्षेत्र में रहने वाले एक रिटायर्ड शिक्षक से फेसबुक के जरिये पेंशन कार्ड बनाने के नाम पर 5 लाख 90 हजार की ठगी कर ली थी। इसके बाद रिटायर्ड शिक्षक ने परपा थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामला दर्ज होने के 20 दिन बाद ही पुलिस जामताड़ा के इन शान्तिर आरोपियों तक पहुंच गई और इन्हें हथदबोचा। इन आरोपियों के खिलाफ अलग-अलग राज्यों में भी कई सायबर अपराध के मामले दर्ज हैं।

दुर्ग में नाबालिग की हत्या का आरोपी फरार इनाम घोषित

दुर्ग। दुर्ग पुलिस ने नाबालिग की हत्या के एक गंभीर मामले में फरार आरोपी की गिरफ्तारी के लिए 10 हजार रुपए के नकद इनाम की घोषणा की है। नाबालिग आरोपी के घर में मृत अवस्था में मिली थी। मृतिका की मां ने आरोपी रविदास पर मारपीट और काम कराकर पैसे न देने का आरोप लगाया था। वहीं एएसपी शोभराज अशवाल ने बताया कि नाबालिग का शव 26 सितंबर 2026 को कोतवाली थाना क्षेत्र के बावड 7 के एक घर में मिला था। हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश तेज कर दी है। पुलिस ने स्पष्ट किया है कि सूचना देने वाले का नाम और पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाएगी।उन्होंने ने नागरिकों से अपील की है कि आरोपी के बारे में कोई भी विश्वसनीय जानकारी होने पर तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 94791-92099 या थाना दुर्ग के नंबर 94791-92019 पर संपर्क करें। दुर्ग के पुलगांव थाना क्षेत्र में मछुआरों पर बारदार हथियार से हमला कर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है।

5 बैगा बच्चों की मौत , कवर्धा कांग्रेस ने बनाई जांच टीम

कवर्धा। कबीरधाम का नंदनी कुमान गांव बैगा बहुल गांव है। यहां आदिवासी बैगा समुदाय के लोग रहते हैं जिन्हें राष्ट्रपति का दत्तक पुत्र भी कहा जाता है। बीते 5 महीनों के दौरान यहां पर 5 बैगा बच्चों की मौत हो चुकी है। कांग्रेस का आरोप है कि जिन पांच बैगा बच्चों की मौत हुई है, वो कुपोषण के चलते हुई है। फिलहाल कुपोषण से लड़ रहे 15 बैगा बच्चों का इलाज बोड़ला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एनआरसी में चल रहा है। एकसर्चों डॉक्टरों की टीम कुपोषित बच्चों का ध्यान यहां रख रहे हैं। बच्चों को डॉक्टरों की निगरानी में बेहतर पोषण आहार दिया जा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द स्वस्थ हो सकें। 5 बैगा बच्चों की मौत के बाद इसपर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने घटनाक्रम की जांच के लिए 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। कांग्रेस की जांच टीम में 2 पूर्व विधायकों सहित जिला कांग्रेस अध्यक्ष नवीन जायसवाल का नाम भी शामिल है। ये टीम जल्द ही नंदनी कुमान गांव का दौरा कर रिपोर्ट तैयार कर पार्टी के आला नेताओं को सौंपेगी।

छत्तीसगढ़ की क्रिस्टीना पर आया नीदरलैंड के क्रिस्टीयान का दिल

जांजगीर-चांपा। गांव की गलियों से निकलकर सात समंदर पार तक पहुंचने वाली प्रेम कहानी अक्सर फिल्मों या उपन्यासों में पढ़ने को मिलती है, लेकिन छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में यह हकीकत बनकर सामने आई है। जिले के पामगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले छोटे से गांव भुईगांव की एक बेटी ने यूरोप के नीदरलैंड से आए युवक को अपना जीवनसाथी चुना है। दो अलग-अलग देशों, संस्कृतियों और हजारों किलोमीटर की भौगोलिक दूरियों से जुड़े इन युवाओं के विवाह ने अब स्थानीय स्तर पर लोगों का खूब ध्यान खींचा है। मिली जानकारी के मुताबिक, पामगढ़ तहसील के भुईगांव स्थित वार्ड क्रमांक 07, नालापारा की रहने वाली 25 वर्षीय क्रिस्टीना नथैनियल ने नीदरलैंड निवासी 32 वर्षीय क्रिस्टीयान एन्डीयश के बरबूम के साथ सात जन्मों तक साथ निभाने



का फैसला किया है। क्रिस्टीना के पिता का नाम हनोक नथैनियल और माता का नाम सोनिया नथैनियल है, जबकि उनके जीवनसाथी बने क्रिस्टीयान के पिता का नाम विलेम डीकॅ वरबूम है। एक तरफ छत्तीसगढ़ का ग्रामीण परिवेश और दूसरी तरफ यूरोप का विकसित देश नीदरलैंड—इन दोनों के बीच भाषा, खानपान, रहन-सहन और सामाजिक परंपराओं का बड़ा अंतर है। इसके बावजूद दोनों ने अपने रिश्ते को मुकम्मल करने का फैसला किया। इस

समक्ष उपस्थित हुए। निर्धारित कानूनी प्रावधानों और अधिनियम की धारा-5 के तहत तीन गवाहों की मौजूदगी में वैधानिक घोषणा की गई।

इस पूरी प्रक्रिया के दौरान वधू पक्ष की ओर से हनोक नथैनियल और सोनिया नथैनियल गवाह के रूप में शामिल हुए। सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद विवाह अधिकारी ने प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर किए और आधिकारिक रूप से विवाह का प्रमाण-पत्र जारी किया। इस

प्रक्रिया के साथ ही दोनों का रिश्ता केवल व्यक्तिगत सहमति तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसे कानूनी और आधिकारिक मान्यता भी मिल गई।

जब भुईगांव जैसे छोटे से ग्रामीण इलाके में यह खबर पहुंची कि यहां की बेटी ने नीदरलैंड के युवक से विवाह कर लिया है, तो गांववालों के बीच उत्सुकता और चर्चा का दौर शुरू हो गया। स्थानीय लोग इस अनोखे रिश्ते को लेकर तरह-तरह की चर्चा कर रहे हैं और नवविवाहित जोड़े को भविष्य के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं। हालांकि, दोनों की मुलाकात कहां और किन परिस्थितियों में हुई थी, इसे लेकर अभी कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन इस शादी ने यह जहर साबित कर दिया है कि जीवनसाथी चुनने में सरहदें और भौगोलिक दूरियां अब कोई बड़ी बाधा नहीं रहें।

भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बने सुनील मिंज

रायगढ़। भारत आदिवासी पार्टी ने सुनील मिंज को प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। राज्य एकीकरण समिति के अनुमोदन एवं निर्देशन के उपरांत उन्हें यह दायित्व अगले आदेश तक के लिए दिया गया है। पार्टी ने उनसे संगठन के प्रति निष्ठा और प्रतिबद्धता बनाए रखते हुए अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करने की अपेक्षा की है।

सुनील मिंज को जनप्रतिनिधि चयन प्रणाली, सामाजिक व्यवस्था और संगठन की अनुशासन नियमावली का पालन सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करना होगा। पार्टी ने उम्मीद जताते हुए निष्ठापूर्वक निर्वहन करेंगे और संगठन के निर्धारित नियमों एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य



करेंगे। प्रदेश उपाध्यक्ष की यह जिम्मेदारी पूर्णतः अवैतनिक रहेगी। यानी इस पद के लिए किसी प्रकार का वेतन या पारिश्रमिक निर्धारित नहीं किया गया है।

पार्टी की ओर से सुनील मिंज को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके

उज्ज्वल भविष्य की कामना की गई है। उनकी नियुक्ति को संगठनात्मक जिम्मेदारी के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, पार्टी की आगामी गतिविधियों और संगठन विस्तार को लेकर उनकी भूमिका के संबंध में फिलहाल कोई अतिरिक्त जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है।

संक्षिप्त समाचार

सोमवार को दो घंटे के लिए खुला रहेगा अम्बेडकर अस्पताल का बाह्य रोगी विभाग

रायपुर। मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय, रायपुर का बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) सोमवार, 19 अक्टूबर को पूर्व की भांति खुली रहेगी।

दरअसल रविवार और सोमवार को महाअष्टमी पर्व पर स्थानीय अवकाश एवं मंगलवार को दशहरा पर्व पर सामान्य अवकाश, इस प्रकार निरंतर तीन दिवस का अवकाश होने के फलस्वरूप सोमवार को बाह्य रोगी विभाग सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक पूर्व की भांति खुली रहेगी। मरीज निर्धारित समय के दौरान चिकित्सकीय परामर्श एवं उपचार के लिए अस्पताल पहुंच सकते हैं। वहीं चिकित्सालय की आपात चिकित्सा सेवा (इमर्जेंसी सर्विस) पूर्व की भांति 24 घंटे जारी रहेगी।

सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के निराकरण को लेकर शासन गंभीर

रायपुर। नागरिकों द्वारा सीएम हेल्पलाइन-1076 पर दर्ज कराई गई शिकायतों के समाधान को लेकर राज्य शासन बेहद गंभीर है। पोर्टल पर दर्ज शिकायतों का संबंधित विभागों द्वारा सक्रियता और गंभीरता से निराकरण किया जा रहा है। लोक निर्माण विभाग ने सीएम हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतों के असंतोषप्रद समाधान और लापरवाही पर 13 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनमें तीन अधीक्षण अभियंता, पांच कार्यपालन अभियंता और पांच अनुविभागीय अधिकारी शामिल हैं। सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों को बिना सारगर्भित टीप के बंद किए जाने के कारण लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिकारियों के विरुद्ध ये कार्रवाई की गई है। सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर विगत दो महीनों अगस्त और सितम्बर माह में लोक निर्माण विभाग से संबंधित शिकायतों की समीक्षा में पाया गया कि एल-1, एल-2 और एल-3 स्तर पर शिकायतों को ऐसी टीप के साथ बंद किया गया है, जो शिकायत का समाधान नहीं दर्शाती है। विभाग ने एल-1 स्तर पर शिकायतों के असंतोषप्रद समाधान पर राष्ट्रीय राजमार्ग उप संभाग बिलासपुर के अनुविभागीय अधिकारी श्री अतुल राज पेगवार, बेमेतरा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री राजेश कुमार बाजपेयी, पेंड्रा उप संभाग के अनुविभागीय अधिकारी श्री जगदीश प्रसाद, सेतु उप संभाग दुर्ग के अनुविभागीय अधिकारी श्री अशोक कुमार हरियाले और पाटन उप संभाग की अनुविभागीय अधिकारी श्रीमती सोनल ढालेन्द्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

महिला कृषक सेवा महाकुंभ एवं कृषक संगोष्ठी में महिला कृषक शामिल हुईं

रायपुर। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2026 को अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष घोषित किए जाने के अवसर पर स्वामी विवेकानंद परिसर स्थित कृषि महाविद्यालय, जोरा में महिला कृषक सेवा महाकुंभ एवं कृषक संगोष्ठी आयोजित की गई। कृषि विभाग, जिला रायपुर और कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर के संयुक्त तत्वावधान में हुए इस कार्यक्रम में जिले की कृषि एवं उससे जुड़े क्षेत्रों की लगभग 300 महिला कृषकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में जिला पंचायत उपाध्यक्ष संदीप यदु मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। विशेष अतिथि के रूप में कृषि स्थायी समिति के सभापति एच सीरुम साहेब, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष अनिमेष कश्यप, रिसर्च संचालक विवेक कुमार त्रिपाठी, एस.एस. टुटेजा, संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग श्रीमती गोपिका गबेल और कृषि महाविद्यालय रायपुर की अध्यक्षता श्रीमती आरती गुहा उपस्थित रहीं। उप संचालक कृषि श्री सतीश अवस्थी ने महिला कृषकों को खाद बिस्की के लिए लागू टोकन सिस्टम की कार्यप्रणाली और इसके लाभों की जानकारी दी। तकनीकी सत्र में प्रधान वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) श्री संजय द्विवेदी ने फसल विविधीकरण एवं दलहन की खेती, वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. गौतम राय ने गौपासन और उत्पादों के विक्रय, तथा वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) डॉ. नीतीश तिवारी ने प्राकृतिक खेती एवं खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताया।

महिला योग भवन व महतारी सदन का संचालन

गोदावरी इस्पात के सीएसआर फंड से होगा

रायपुर। रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विप्र नगर में नवनिर्मित महिला योग भवन एवं महतारी सदन के संचालन की जिम्मेदारी गोदावरी इस्पात समूह द्वारा सीएसआर (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व) फंड के माध्यम से निभाई जाएगी। इस पहल से क्षेत्र की महिलाओं, कमजोर आय वर्ग के परिवारों और जरूरतमंद लोगों को इस आधुनिक भवन का लाभ उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। इस संबंध में आयोजित समारोह में रायपुर पश्चिम के विधायक राजेश मृण्त, नगर निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मोनल चौबे, नगर निगम सभापति श्री सूर्यकांत राठौर सहित जनप्रतिनिधि एवं संबंधित संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

विप्र नगर में निर्मित यह भवन अपनी आकर्षक वास्तुकला, सुव्यवस्थित संरचना और जनहित से जुड़ी उपयोगिता के कारण रायपुर पश्चिम की एक विशिष्ट पहचान बन रहा है। इसे क्षेत्र की आइकॉनिक बिल्डिंग के रूप में देखा जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य केवल एक



सुंदर भवन तैयार करना नहीं, बल्कि इसे बेहतर प्रबंधन के माध्यम से जनसुविधा और सामाजिक गतिविधियों का उपयोगी केंद्र बनाना है। विधायक राजेश मृणत की प्रारंभ से ही यह मंशा रही है कि रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में विकसित होने वाली आधुनिक सुविधाओं का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को भी ऐसी सुविधाएं मिलें, जिनका लाभ सामान्यतः बड़े संसाधनों वाले वर्गों को उपलब्ध होता है। महिला योग भवन एवं महतारी सदन इसी सोच को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

मिशन 2028 की तैयारी, दो दिन रायपुर में रहेंगी प्रभारी स्मृति ईरानी : पुरंदर

सांसद-विधायक के अलावा पदाधिकारियों से बैठक कर लेंगी फीडबैक

रायपुर। छत्तीसगढ़ भाजपा में मिशन 2028 की तैयारी ने गति पकड़ ली है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने बताया कि नवनिर् चुक छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी स्मृति ईरानी दो दिवसीय दौरें पर रायपुर आएंगी। 25 और 26 अक्टूबर को अपने प्रवास के दौरान रायपुर में चुनावी रणनीति पर पूर्व सांसदों और विधायकों से वन-टू-वन चर्चा करेंगी। स्मृति ईरानी संगठन के पदाधिकारियों से फीडबैक लेंगी। इसके साथ प्रदेश के 60 से ज्यादा पूर्व सांसद-विधायकों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने मीडिया से चर्चा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरें को लेकर बताया कि राष्ट्रपति 22-23 अक्टूबर को रायपुर और जगदलपुर में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगी। दोपहर 12:45 बजे



रायपुर के लोक भवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होगी। पूज्य माता हासी देवी जी के सम्मान में 200 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करेंगी।

इसके अलावा 4 बजे वे रायपुर के इंडोर स्टेडियम में नुआखाई पर्व के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगी। 'सेवा सम्मान पर्व' एवं 'युवा प्रबोधन' कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। 23 अक्टूबर को राष्ट्रपति सुबह 11 बजे जगदलपुर स्थित मां दत्तेश्वरी मंदिर में पूजा-अर्चना

निकाय चुनाव की तैयारी तेज, भाजपा की बैठक में बनी जीत की रणनीति

■ सांसद संतोष पांडेय ने कहा - सभी 17 निकायों में जीतेगे

रायपुर। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आज राजधानी रायपुर स्थित भाजपा प्रदेश मुख्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में संगठन की बड़ी बैठक हुई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने पदाधिकारियों और जिला प्रभारियों के साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की। बैठक में सांसद और विधायक भी शामिल हुए।

भाजपा ने प्रदेश के सभी 17 नगरीय निकायों में जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा है। भाजपा प्रदेश मुख्यालय में हुई बैठक में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारियों और आगामी रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह के साथ प्रदेश महामंत्री यशवंत जैन, अखिलेश सोनी, डॉ. नवीन



मार्कंडेय, प्रदेश उपाध्यक्ष जगन्नाथ पाणिग्रही और क्रेडा अध्यक्ष भूपेन्द्र सक्नी सहित संगठन के कई पदाधिकारी मौजूद रहे।

जिला प्रभारियों के साथ कुछ सांसद और विधायकों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। बैठक के बाद भाजपा के मुख्य प्रवक्ता और सांसद संतोष पांडेय ने कहा कि प्रदेश के नगरीय निकायों में लगातार विकास कार्य हो रहे हैं। युशासन के मामले में कहीं कोई कमी नहीं है। नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में विकास कार्यों के आधार पर भाजपा सभी 17 नगरीय निकायों में जीत हासिल करेगी।

प्रतिभा बड़े शहरों की मोहताज नहीं: मंत्री अग्रवाल

■ सही अवसर और मार्गदर्शन मिले तो सरगुजा का बच्चा भी देश में बना सकता है अपनी अलग पहचान

रायपुर। सरगुजा जिले के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के डॉक्टर और इंजीनियर बनने के सपनों को साकार करने की दिशा में पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल के मार्गदर्शन में एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक पहल की गई है। अब जिले के शासकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को नोट एवं जेईई जैसी प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की आवश्यकता कम होगी। उन्हें अपने विद्यालयों में ही आधुनिक स्मार्ट क्लासरूम, विषय विशेषज्ञ शिक्षकों और नवीनतम डिजिटल तकनीक के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण कोचिंग की सुविधा मिलेगी।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने शनिवार को जिला कलेक्टरेट सभाकक्ष में आयोजित कार्यक्रम में सरगुजा जिले के 35 शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में नोट एवं जेईई की नि:शुल्क लाइव ऑनलाइन कोचिंग का शुभारंभ किया। जिला



खनिज संस्थान न्यास एवं स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में शुरू की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना से लगभग 2,120 विद्यार्थियों को दो वर्षों तक प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर मिलेगा।

यह पहल विशेष रूप से उन प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी, जो आर्थिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों के कारण बड़े शहरों में जाकर महंगी कोचिंग प्राप्त नहीं कर पाते। अब सरगुजा के विद्यार्थियों को अपने ही विद्यालय में राष्ट्रीय स्तर के शिक्षकों से पढ़ने, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और अपनी प्रतिभा को निखारने का अवसर प्राप्त होगा।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि यह केवल एक शैक्षणिक परियोजना का शुभारंभ नहीं, बल्कि सरगुजा के हजारों बच्चों के सपनों को नई उड़ान देने का संकल्प है।

भिलाई स्टील प्लांट मुद्दा: भाजपा विधायक रिकेश सेन देंगे भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के निवास पर धरना!

रायपुर। छत्तीसगढ़ के भिलाई स्टील प्लांट (बीएसपी) के निजीकरण का मुद्दा इन दिनों सियासी गलियारों में खूब गरमाया हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पीसीसी चीफ दीपक बैज ने बीएसपी के निजीकरण का आरोप लगाया था। इसे लेकर अब रिसाली से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पोस्ट किया है। उन्होंने भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के घर के सामने धरना देने की बात कही है।

रिसाली विधानसभा से भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसने राजनीतिक गलियारों में तापमान फिर बढ़ा दिया। उन्होंने लिखा कि भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के निवास के सामने धरना जल्द दूंगा, आपने अफवाह उड़ाया कि भिलाई इस्पात संयंत्र बिक रहा है। फिलहाल वह भूपेश बघेल और देवेंद्र यादव के घर किस दिन धरना दूंगा यह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। हालांकि 'जल्द' ही प्रदर्शन की बात कही है।



बीएसपी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया था। इसमें बघेल ने लिखा कि उन्हें जानकारी मिली है कि एक उद्योगपति भिलाई इस्पात संयंत्र देखने आने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि देश बेचने का अभियान चला रहे नरेंद्र मोदी की नजर अब हमारे बीएसपी पर है और उनके प्रिय खरीददार मुआनका करने आ रहे हैं। बघेल ने आगे लिखा है कि मोदी जी समझ लें कि बीएसपी छत्तीसगढ़ की आत्मा है और हम छत्तीसगढ़वासी इसे किसी

हेल्पलाइन आम लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य लोगों को घर बैठे उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना है। अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वे शिकायतों को गंभीरता से लें और समय पर उनका निराकरण करें।

ए स ए स आ र

अभियान को लेकर कांग्रेस द्वारा किए गए अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीद रही है। वर्तमान सरकार कांग्रेस की तुलना में अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीद रही है। सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के निलंबन को लेकर भी राजस्व मंत्री ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निलंबन की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम



वर्तमान सरकार कांग्रेस की तुलना में अधिक कीमत पर किसानों से धान खरीद रही है।

सीएम हेल्पलाइन में शिकायतों के निराकरण में लापरवाही के मामले में तहसीलदार प्रमोद कुमार चंद्रवंशी के निलंबन को लेकर भी राजस्व मंत्री ने बयान दिया है।

उन्होंने कहा कि निलंबन की कार्रवाई से स्पष्ट संदेश गया है कि सरकारी कामकाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीएम

सूरत में बिकने नहीं देंगे। किसी भी सूरत में नहीं। यह बात छत्तीसगढ़ भाजपा के नेता भी समझ लें कि बीएसपी बिकाऊ नहीं है।

पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी भूपेश बघेल का समर्थन करते हुए सवाल उठाया था कि क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि भिलाई स्टील प्लांट और एनएमडीसी को नहीं बेचा जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि अब भिलाई स्टील प्लांट को लेकर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं।

कांग्रेस नेताओं के आरोपों के बाद अब भाजपा विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव के घर के बाहर धरना देने की बात कही है। हालांकि देखा होगा कि कब वह धरना की तारीख और समय की घोषणा करते हैं।

सवालों के घेरें में सीजीपीएससी! पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से क्यों मिले अभ्यर्थी?

रायपुर। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) एक बार फिर से सवालों के घेरें में है, क्योंकि सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। चलिए जानते हैं कि आखिर अभ्यर्थियों ने पूर्व सीएम से क्यों मुलाकात की है।

दरअसल, सीजीपीएससी

मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों ने शनिवार को भिलाई में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान अभ्यर्थियों ने परीक्षा की उत्तरपुस्तिकाओं के पुनर्मूल्यांकन और साक्षात्कार से पहले सूचना के अधिकार (आरटीआई) के माध्यम से अपनी उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग की।

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने अभ्यर्थियों की मांगों के समर्थन में उनके साथ खड़े रहने की बात कही। उन्होंने



अपने सोशल मीडिया फेसबुक पर पोस्ट करते हुए लिखा आज भिलाई निवास में सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 के अभ्यर्थियों से भेंट-मुलाकात हुई।

उन्होंने आगे लिखा कि अपनी मेहनत से अपने भविष्य और न्याय की उम्मीद लेकर पहुंचे युवाओं ने पुनर्मूल्यांकन तथा साक्षात्कार से पूर्व आरटीआई के माध्यम से उत्तरपुस्तिकाओं की कॉपी उपलब्ध कराने की मांग रखी। युवा साथियों के साथ हम सब खड़े हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना से साकार हुआ सेवाराम का पक्के घर का सपना

रायपुर। प्रधानमंत्री आवास योजना जरूरतमंद परिवारों के पक्के घर के सपने को साकार कर उनके जीवन में खुशियां ला रही है। मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिले के विकासखंड अंबागढ़ चौकी अंतर्गत ग्राम सेवहारबांधा निवासी श्री सेवाराम के लिए भी यह योजना खुशियों की सौगात लेकर आई है। योजना के तहत पक्का मकान मिलने से उनके परिवार को सुरक्षित आशियाना मिला है और वर्षों से अपने घर में रहने की इच्छा पूरी हुई है। श्री सेवाराम के लिए पक्का मकान बनाना एक बड़ा सपना था। सीमित संसाधनों के बीच परिवार की जरूरतों को पूरा करते हुए स्वयं का पक्का घर बनाना आसान नहीं था। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलने से उनकी यह चिंता दूर हुई है। अब उनका परिवार अपने पक्के घर में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर रहा है।

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं ज्योति कुशवाहा (पुराना नाम जिसे बदला जाना है) उम्र 23 वर्ष पति-सोनू कुशवाहा, पता-म.नं.3007, बाड़ी-14, राजीव नगर, मोहबा, वाजरा, थाना-आमानाका, पोस्ट-टाटीबंध, तहसील व जिला-रायपुर, राज्य-छत्तीसगढ़ पिन कोड 492099 ने अपना (पुराना नाम) कोयारी ज्योति KOYARI JYOTI को बदलकर (नया नाम) ज्योति कुशवाहा JYOTI KUSHAWAHA रख लिया है।

ज्योति कोयारी मोहबा बाजार, रायपुर

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं राजकुमार मनहरे उम्र 38 वर्ष पिता-समारा मनहरे, निवासी ग्राम व पोस्ट कोसरंगी, तहसील- आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-493225 ने अपने नाबालिग पुत्री का (पुराना नाम) कावेरी मनहरे KAVERI MANHARE से बदलकर (नया नाम) पूनम मनाडे POONAM MANNADE रख लिया है।

राजकुमार मनहरे कोसरंगी, आरंग

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं हेमलता उम्र 37 वर्ष पति स्व.विनोद सोनकर, निवासी ग्राम पारागाँव-1 (पारागाँव), तहसील-आरंग जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-493441 ने अपने नाबालिग पुत्री का (पुराना नाम) भूमि सोनकर BHUMI SONKAR से बदलकर (नया नाम) भूमिका सोनकर BHUMIKA SONKAR रख लिया है।

हेमलता सोनकर पारागाँव, आरंग

प्रारूप (एक)

समाचार प्रपत्र में प्रकाशित की जाने वाली सूचना

मैं डामेश्वर साहू उम्र 38 वर्ष पिता-केसलाल साहू, निवासी कागदेही वार्ड-13, नगर पंचायत समोदा, तहसील आरंग, जिला-रायपुर, छत्तीसगढ़ पिन कोड-493441 ने अपने नाबालिग पुत्र का (पुराना नाम) आकाश साहू AKASH SAHU से बदलकर (नया नाम) त्रिलोक साहू TRILOK SAHU रख लिया है।

डामेश्वर साहू समोदा, आरंग

न्यायालय तहसीलदार गोबरा नवापारा

मामले की श्रेणी: राजस्व संदर्भ : जिला रायपुर तहसील-गोबरा नवापारा प.ह.न.-00010 खोला ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्रकरण क्रमांक-सौजी-2026-27-057-1-3265

ईशतहरा

तहसील गोबरा नवापारा के प.ह.न. 00010 के अंतर्गत ग्राम खोला के वर्तमान भूमिस्वामी राजू दीनर पिता/पति-वीरवल दीनर पता-नाहनचंडी अन्धनपुर के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 903/1(0.2200) में प्रस्तावित भूमिस्वामी/केता इन्द देव प्रसाद पिता-पति-रामचन्द्र प्रसाद पता-सुरधि नगर नायकबांधा अन्धनपुर के नाम पर पंजीयन/पंजी होने के उपरान्त नामांतरण / अभिलेख दुरुस्ती / खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में दर्ज विचारधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 02/11/2026 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय तहसीलदार गोबरा नवापारा पर की जावेगी।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/स्था को कोई दवाा आपत्ति हो तो इशतहार प्रकाशन उपरान्त प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दवाा आपत्ति स्वयं / अधिका / आममुख्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरान्त प्राप्त दवाा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह इशतहार मे इतहास एंव पट्टदवा से आज दिनांक 17/10/2026 को जारी किया जाता है।

तहसीलदार Chandrashekhar Mandai गोबरा नवापारा

लोकतंत्र की लड़ाई में सरकार को बड़ी चुनौती

सनत जैन

भारत में एक बार फिर 1975 जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। सरकार के खिलाफ हर वह वर्ग सामने खड़ा होता हुआ दिख रहा है, जो इस तरह के आंदोलन में कभी शामिल नहीं होता। सारे देश में जितने भी विपक्षी दल हैं इस समय सरकार के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। उसमें विचारधारा का कोई महत्व नहीं रह गया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने प्रेस कांफ्रेंस के दौरान यह कहकर सनसनी मचा दी है, लोकतंत्र को बचाने की इस लड़ाई में सभी लोग शामिल हों। कांक्रोच जनता पार्टी के नेतृत्व में यह लड़ाई लड़ी जाएगी। इसमें सभी विपक्षी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, अधिवक्ता यहां तक कि बार काउंसिल के अधिवक्ता भी इस आंदोलन में शामिल हों। दिल्ली के प्रेस क्लब में कांक्रोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की पत्रकार-वार्ता को वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण, दक्षिण के अभिनेता प्रकाश राज, छात्र नेता नेहा बोरा जब संबोधित कर रहे थे उसी समय कुछ लोगों ने पत्रकार वार्ता में व्यवधान पैदा किया। उसके बाद प्रशांत भूषण उत्तेजित हो गए और उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया कि लोकतंत्र की इस लड़ाई में अब सभी वर्गों को बिना किसी भेदभाव के शामिल होना होगा। यह लड़ाई अब युवाओं के नेतृत्व में लड़ी जाएगी। किसी भी विचारधारा या कोई मतभेद अब इस लड़ाई में बाधा नहीं बनेंगे। सरकार और पुलिस को बर्बरता को सहन नहीं किया जाएगा। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग द्वारा जो गड़बड़ी की गई है उसे रोकने और सही कराने के साथ-साथ वॉलेट पेपर से चुनाव करने और ईवीएम का बहिष्कार करने का आंदोलन छेड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि हम सरकार को हटाने के लिए यह आंदोलन करेंगे। सरकार से हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। लोकतंत्र की इस लड़ाई को लड़ने के लिए अब सभी को एकजुट होकर सड़कों पर आना पड़ेगा। जिस तरह से चुनाव आयोग की गड़बड़ियों को लेकर ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग से जो आंदोलन शुरू हुआ था अब वह आंदोलन बड़ी तेजी के साथ सभी वर्गों के बीच में फैलता चला जा रहा है। विशेष रूप से ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी अब खुलकर सामने आ गए हैं। वह भी प्रदर्शन में शामिल हो गए हैं। वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा यह भी आह्वान किया गया है कि जब लोकतंत्र खतरे में हो ऐसी स्थिति में बार काउंसिल को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। इस लड़ाई में बाकी भी शामिल हों अन्यथा लोकतंत्र को बचा पाना संभव नहीं होगा। जिस तरह से सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, सामाजिक संगठन भी इन आंदोलन और प्रदर्शनों में शामिल हो रहे हैं। यह आंदोलन केवल दिल्ली में नहीं चल रहा है, इसकी आग कई राज्यों में फैल चुकी है। ऐसी स्थिति में दिनों दिन स्थिति खराब होती जा रही है। ज्ञानेश कुमार को बचाने के चक्कर में जहां एक ओर सरकार के लिए चुनौतियां और पेशानी बढ़ रही है वहीं अब इसकी आंच न्यायपालिका के ऊपर भी देखने को मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट में वकीलों के दो वर्ग आमने-सामने आ गए हैं। एक सीधे-सीधे मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत का इस्तीफा मांग रहा है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और एसआईआर को लेकर जो सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, वह लंबे समय से मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी की खंडपीठ में चल रही है। वकीलों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट कहीं ना कहीं ज्ञानेश कुमार को बचाने का काम कर रही है। इसका आरोप अब सीधे-सीधे मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जा रहा है, जिसके कारण स्थिति दिन-प्रतिदिन सरकार के साथ-साथ अब न्यायपालिका के लिए भी चुनौती के रूप में देखने को मिल रही है।

भारतीय दार्शनिक समुदाय

19- थेरावाद या प्रारम्भिक पाली बौद्धधर्म

गतांक से आगे...

अन्त में बोधि वृक्ष के नीचे वैशाख की पूर्णिमा के दिन उन्हें बोधि, तत्त्वज्ञान हुआ। उसके बाद उन्होंने जगत् के सामने निम्न चार आर्यसत्य प्रस्तुत किये, जो बौद्धधर्म और बौद्धदर्शन का आधार हैं – (1) दु:ख, (2) दु:ख हेतु, (3) दु:ख निरोध, (4) दु:ख निरोध का उपाय।

जरा मृत्यु रूप दु:ख संसार में प्रत्यक्ष है। बुद्ध ने दु:ख का हेतु ढूँढ निकाला। हेतु या कारण को बुद्ध ने प्रतीत्यसमुत्पाद के रूप में बताया। प्रतीत्य का अर्थ है कि ऐसा होने पर (अर्थात् कार्य के प्रति कारणों के इकट्ठा होने पर) समुत्पाद अर्थात् उत्पन्न होना। प्रश्न यह था कि किन बातों के होने पर (1) जरा मरण रूप दु:ख उत्पन्न होता है, बुद्ध ने उत्तर दिया कि (2) जाति (जन्म) के होने पर जरा मरण रूप दु:ख होता है। जन्म क्या होने पर होता है, बुद्ध का उत्तर था कि (3) भव अर्थात् पूर्वकालीन अस्तित्व होने पर। भव

का कारण है (4) उपादान अर्थात् आसक्ति। और उपादान का कारण है (5) तृष्णा अर्थात् विषयों की कामना। और तृष्णा का कारण है (6) वेदना अर्थात् सुख दु:ख का अनुभव। इस वेदना का कारण है (7) स्पर्श अर्थात् इन्द्रिय और विषयों का संयोग। %स्पर्श% का कारण है (8) वडायतन% अर्थात् 6 इन्द्रियों के रूप में 6 स्पर्श के आधार । षडायतन का कारण है (9) नामरूप अर्थात् भौतिक और मानसिक स्कन्ध (क्षणिक धाराएं)। नामरूप का कारण है (10) विज्ञान अर्थात् चेतना अर्थात् बिना चेतना के नामरूप नहीं हो सकते। विज्ञान का कारण है (11) संस्कार अर्थात् वस्तुओं के अनुभव से उत्पन्न हुए संस्कार, यदि संस्कार न हों तो विज्ञान नहीं हो सकता। संस्कार का कारण है (12) अविद्या अर्थात् अनादि काल से चला आता हुआ अज्ञान। इस प्रक्रर 12 अरों त्राले इस संसार चक्र का मूल कारण अविद्या है।

क्रमशः...



धर्मचक्र

न्यायपालिका को डराने की कोशिशें बेअसर, कानून से ऊपर कोई नहीं

कातिलाल मांडेठ

देश में चुनाव प्रक्रिया और मतदाता सूची के विषय गहन पुनरीक्षण को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की टिप्पणी ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता और संवैधानिक मर्यादा को लेकर महत्वपूर्ण संदेश दिया है। राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं के विरोध मार्च से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि अदालत को डराने या धमकाने की कोशिशों का कोई असर नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि न्यायालय को इस बात की पूरी जानकारी रहती है कि उत्प्रेरके बाहर क्या कहा जा रहा है और अदालत के भीतर क्या हो रहा है। न्यायपालिका किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं रहती, बल्कि परिस्थितियों और घटनाक्रम से भलीभांति परिचित रहती है।

मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी ऐसे समय आई है, जब मतदाता सूची के विषय गहन पुनरीक्षण को लेकर सात्पाक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ा हुआ है। विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। इस मुद्दे पर राजनीतिक विरोध, जापन और मार्च के बाद मामला न्यायालय तक पहुंचा है। ऐसे माहौल में सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी का महत्व इसलिए बढ़ जाता है, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक असहमति और न्यायिक प्रक्रिया दोनों का अपना अलग स्थान है।

लोकतंत्र में विरोध करना राजनीतिक दलों और नागरिकों का अधिकार है, लेकिन विरोध की अभिव्यक्ति ऐसी होनी चाहिए, जो संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा और कानून की सीमाओं का सम्मान करे। किसी निर्णय से असहमति होने पर संबंधित संस्था के सामने तथ्य रखना, कानूनी उपाय अपनाना और न्यायालय में याचिका दायर करना लोकतांत्रिक व्यवस्था का स्वाभाविक हिस्सा है। इसके विपरीत किसी संस्था पर दबाव बनाने अथवा उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित करने का प्रयास



स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुकूल नहीं माना जा सकता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता केवल न्यायाधीशों का विषय नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा से जुड़ी हुई है। विपक्षी नेताओं ने विशेष गहन पुनरीक्षण से जुड़े चुनाव आयोग के फैसलों को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। इसमें प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने, मतदाता सूची से नाम हटाने के नियमों का पालन सुनिश्चित करने, हटाए गए नामों का विवरण सार्वजनिक करने और मतदाता संबंधी आंकड़ों की स्वतंत्र जांच कराने जैसी मांगें उठाई गई हैं। याचिकाकर्ताओं ने सुनवाई पूरी होने तक इस प्रक्रिया पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध भी किया है। न्यायालय ने मामले में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इससे स्पष्ट है कि विवाद का समाधान अब संवैधानिक और न्यायिक प्रक्रिया के माध्यम से तलाशा जाएगा।

यहां एक महत्वपूर्ण बात समझने की आवश्यकता है कि न्यायालय में याचिका दायर करना किसी पक्ष के आरोपों को स्वतः सही सिद्ध नहीं करता। इसी तरह किसी प्रक्रिया पर सवाल उठने मात्र से उसे गलत नहीं माना जा सकता। आरोपों, तथ्यों और संबंधित कानूनों की जांच के बाद ही न्यायालय किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसलिए सभी पक्षों को न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। लोकतंत्र में संस्थाओं के प्रति विश्वास बनाए रखने के लिए यह जरूरी है कि राजनीतिक दलों और कानूनी

ज्ञान/मीमांसा

कांग्रेस और सीजेपी के हालिया प्रदर्शन कितने सफल रहे

सचिन शर्मा

भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को लेकर पिछले दिनों राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रदर्शनों की झड़ी लग गई। पहले ये देश के कुछ हिस्सों तक सीमित थे और ज्यादातर सिर्फ बयानबाजी ही सामने आ रही थी। 10 अक्टूबर को कांक्रोच जनता पार्टी ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के साथ सबसे पहले दिल्ली की सड़कों पर उतरी। उनके साथ ही नीट पेपर लीक मामले में सोनम वांगचुक के साथ अनशन कर चर्चा में आई आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) की अध्यक्ष नेहा बोरा अपने साथी छात्र नेताओं के साथ 10 से 13 अक्टूबर तक कर्नाट प्लेस से संसद के आस-पास तक कई जगहों पर दौड़-भाग करते हुए दिखीं। इन सभी में सबसे बड़ा आंदोलन कांग्रेस का रहा जिसने 12 अक्टूबर को ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पिटिशन फाइल करने के लिए ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट तक मार्च किया बल्कि राहुल गांधी के साथ उनके कई कार्यकर्ता सीप्रीम कोर्ट परिसर में दाखिल भी हो गए। इस बीच राजधानी के लोग खासे परेशान भी रहे। सेंट्रल दिल्ली, जिसमें खान मार्केट से लेकर कर्नाट प्लेस तक के हजारों व्यापारी भी शामिल हैं इन प्रदर्शनों से परेशान रहे। वो अपनी रोजी-रोटी के बारे जाने से हैरान रहे। तो आखिर इन सभी प्रदर्शनों से किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। सरकार के लिए इससे क्या सबक हैं, इसी पर बात करते हैं।

सीजेपी (कांक्रोच जनता पार्टी) के तीन प्रमुख चेहरे अभिजित दीपके, सौरव दास और आशुतोष रांका लगातार केन्द्र सरकार, उसके मुखिया प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आक्रामक भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं। जुलाई 2026 में नीट पेपर लीक मामले को लेकर हुए सीजेपी आंदोलन की वजह से मोदी सरकार की खासी किरकरी हुई थी। उसे तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान का इस्तीफा लेना पड़ा था और जैसे-तैसे उस आंदोलन को शांत कराया गया था। इस बार सरकार सजग थी। उसने संसद से कुछ ही दूरी पर स्थित जंतर-मंतर की किलेबंदी कर दी। वहां सीजेपी को आंदोलन के लिए दिल्ली पुलिस ने अनुमति ही नहीं दी। सीजेपी के तीनों नेताओं को दिल्ली में उनकी फ्लाइट के लैंड करने के तुरंत बाद ही फ्लाइट से ही पकड़ लिया गया और अगले दिन छोड़ा गया। निर्देश विहिन सीजेपी समर्थकों और कार्यकर्ताओं को एक जगह पर इकट्ठा हो



नहीं होने दिया गया। पुलिस ने उन सभी को दिन भर दौड़ाया लेकिन मारा नहीं। जुलाई की तरह कैमरों में पुलिस को लाठी मारते रिकार्ड नहीं किया गया। दिल्ली पुलिस ने बड़ी होशियारी के साथ महिला पुलिस को आगे रखा और पुरुष और महिला कार्यकर्ताओं दोनों को दिल्ली की महिला पुलिस ने ही सबसे ज्यादा डील किया। पिछली बार की डंडे मारने और पैलेट गन चलाने जैसी गलती इस बार दोहराई नहीं गई। सीजेपी के तीनों नेताओं को इस शर्त के साथ बेल बांड भरा कर छोड़ा गया था कि अब वे अगले एक साल तक शांति बनाए रखेंगे। माइलेज ना मिलने से परेशान सीजेपी के सौरव दास और आशुतोष रांका फिर से जंतर-मंतर पहुंच गए। वहां नारे लगाए। सरकार इसी ताक में बैठी थी। उन्हें शांति भंग करने और बेल बांड का पालन ना करने की वजह से 5 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर तिहाड़ जेल भेज दिया गया।

आइसा (ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर इस बार मीडिया खूब मेहरबान रहा। कारण था सीजेपी के प्रमुख नेताओं का मैदान से गायब रहना। कांग्रेस का आंदोलन 12 अक्टूबर को था और कांग्रेस ने सीजेपी का नाम तक नहीं लिया। कांग्रेस सीजेपी को आम आदमी पार्टी की बी-टीम मानती है और उससे दूरी बनाकर रखती है। राहुल गांधी को जब भी सीजेपी का उल्लेख करना होता है तो वो छात्रों की बात करके उसका नाम लेने तक से कन्नी काट जाते हैं। इस बात का नेहा बोरा को खूब फायदा मिला। वो 10 और 11 अक्टूबर को खूब दौड़-भाग करते हुए नजर आईं। उनके %प्लेस प्रोटेस्ट% ऐसे थे जैसे वो दिल्ली पुलिस से लुका छिपी खेल रही हों। पुलिस ने भी उन्हें ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया बल्कि उन्हें सहयोग करती हुई नजर आईं। नेहा को पुलिस कई बार पकड़कर ले गई और थोड़ी देर बाद छोड़ भी दिया। नेहा फिर मैदान में थीं। मीडिया कवरेज के हिसाब से देखें तो नेहा टीवी पर खूब नजर आई हालांकि वो जिन कम्युनिस्ट पार्टियों का प्रतिनिधित्व करती हैं

थॉमस अल्वा एडिसन ने दिए दुनिया को कई क्रांतिकारी आविष्कार

अनन्या मिश्रा

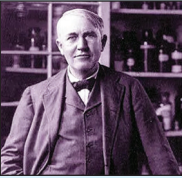
अब तक के सबसे महान वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन का 18 अक्तूबर को निधन हो गया था। उन्होंने अपने जीवनकाल में 1,093 अमेरिकी पेटेंट हासिल किए। थॉमस एडिसन ने दुनिया को बिजली के बल्ब के साथ ही इलेक्ट्रॉनिक पेन, मूवी कैमरा और कार्बन माइक्रोफोन के साथ आ रही हैं। वह वैज्ञानिक होने के साथ-साथ एक बिजनेसमैन भी थे।

अमेरिका के ओहियो राज्य में मिलान शहर में 11 फरवरी 1847 को थॉमस एडिसन का जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल ऑग्डेन एडिसन व मां का नाम नैंसी मैथ्यु इलियट था। वह अपने माता-पिता की 7वीं संतान थे। हालांकि एडिसन की यात्रा इतनी आसान नहीं रही

थी। मंदबुद्धि होने की वजह से एडिसन को स्कूल से निकाल दिया गया था। लेकिन इस दौरान उनकी मां ने उनको घर पर पढ़ाया।

थॉमस एडिशन की मां के निधन के बाद उनको स्कूल के शिक्षक का एक पत्र मिला। जिसमें लिखा था कि एडिसन पढ़ने में काफी कमजोर हैं। यह पढ़कर एडिसन खूब रोए और हार नहीं मानी। उन्होंने शुरूआती दौर में ग्रांड ट्रंक रेल रोड लाइन से यात्रा करने वालों को अखबार बेचने का काम किया। फिर खुद का अखबार शुरू किया और उसका नाम ग्रेंड ट्रंक हेराल्ड रखा। यह उनका पहला व्यावसायिक उपक्रम था।

साल 1877 में थॉमस एडिसन ने टिनफाइल फोनोग्राफ का आविष्कार किया था। जोकि उनका पहला और बड़ा



लिखने और संगीत रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जा सकता है। उनके फोनोग्राफ में एक सिलेंडर का इस्तेमाल होता था। इसमें दो सुइयां लगी थीं और एक सुई से रिकॉर्डिंग होती थी और दूसरी से साउंड प्लेबैक किया जाता था।

बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए 2 हजार से ज्यादा सामान आजमाए। इस दौरान वह हजारों बार फेल हुए और आखिरकार 27 जनवरी 1880 को बल्ब का पेटेंट हासिल किया। बताया जाता है कि उस दौर में इसको बनाने के लिए एडिसन ने 40 हजार

आविष्कार था। एडिसन का यह आविष्कार किसी भी आवाज को रिकॉर्ड करने और बजाने में सक्षम पहली मशीन थी। एडिसन के मुताबिक इस मशीन का इस्तेमाल रश्तलेख, पत्र

लिखने और संगीत रिकॉर्ड करने के लिए भी किया जा सकता है। उनके फोनोग्राफ में एक सिलेंडर का इस्तेमाल होता था। इसमें दो सुइयां लगी थीं और एक सुई से रिकॉर्डिंग होती थी और दूसरी से साउंड प्लेबैक किया जाता था।

बताया जाता है कि थॉमस एडिसन ने बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए 2 हजार से ज्यादा सामान आजमाए। इस दौरान वह हजारों बार फेल हुए और आखिरकार 27 जनवरी 1880 को बल्ब का पेटेंट हासिल किया। बताया जाता है कि उस दौर में इसको बनाने के लिए एडिसन ने 40 हजार

डॉलर से ज्यादा खर्च किया था। इस आविष्कार में हाई रेंजिस्टेंस कार्बन ग्रेड फिलामेंट का इस्तेमाल किया गया था, जोकि 40 घंटे से अधिक समय तक काम करता था।

साल 1899 में थॉमस एडिसन ने वाहनों को बैटरी से चलाने का सपना देख लिया था। इसी साल उन्होंने अल्कलाइन स्टोरेज बैटरी विकसित करना शुरू कर दी थी। वह एक ऐसी बैटरी बनाना चाहते थे, जिसको बिना रिचार्ज किए कार को करीब 100 मील तक चलाया जा सके। लेकिन उस दौर में पेट्रोलियम पदार्थों की प्रचुरता थी, इसलिए इलेक्ट्रिक कार दूर की कौड़ी लगने लगी। वहीं 10 साल तक इस पर काम करने के बाद थॉमस एडिसन ने इसे त्याग दिया।

वहीं 18 अक्तूबर 1931 को 84 साल की उम्र में थॉमस एडिसन की मृत्यु हो गई।

आज का इतिहास

- 1386 जर्मनी में हैडलबर्ग विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी।
- 1564 इंग्लैंड के नौसैनिक कमांडर जॉन हॉकिंस ने दूसरी बार अमेरिका यात्रा शुरू की थी।
- 1878 थॉमस एल्वा एडीसन ने घरेलू उपयोग के लिए बिजली उपलब्ध करायी थी।
- 1891 अमेरिका में पहली अंतरराष्ट्रीय छह दिवसीय साइकिल रेस न्यूयार्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन से शुरू हुयी थी।
- 1898 अमेरिका ने स्पेन से प्यूर्टो रिको को अपने कब्जे में लिया था।
- 1922 ब्रिटिश ब्रांडकास्टिंग कॉर्पोरेशन की स्थापना हुई थी।
- 1944 द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी जर्मनी से चेकोस्लोवाकिया की स्वतंत्रता के लिये सोवियत संघ ने लड़ाई शुरू की थी।
- 1972 हेलिकाप्टर एस ए 315 का बँगलोर में परीक्षण हुआ था।
- 1973 अर्थशास्त्री वैंसिली लिओन्टीफ को अर्थव्यवस्था के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
- 1976 विलियम एन लिप्सकोंब जूनियर को रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया गया था।
- 1989 पूर्वी जर्मनी के कम्युनिस्ट नेता एरिक होनेकर को उनके पद से हटा दिया गया था।
- 1980 पहली हिमालय कार रैली को बम्बई (मुंबई) के ब्रेबोन स्टेडियम से हरी झंडी दिखा कर खाना किया गया था।
- 1991 दक्षिण पश्चिम एशिया और दक्षिणी पूर्वी यूरोप के मुहाने पर स्थित अजरबैजान ने तत्कालीन सोवियत संघ से स्वतंत्र होने की घोषणा की थी।
- 1995 कोलंबिया में गुट निरपेक्ष देशों का ग्यारहवां शिखर सम्मेलन प्रारम्भ हुआ था।
- 1998 भारत और पाकिस्तान आणविक खतरे रोकने के लिए सहमत हुए थे।
- 2000 श्रीलंका में विपक्षी सदस्य अनुरा भंडारानायके को संसद अध्यक्ष बनाने की सहमति थी।
- 2004 कुख्यात चंदन तस्कर वीरप्पन मारा गया था।
- 2004 म्यांमार के प्रधानमंत्री खिन न्युंट को भ्रष्टाचार के आरोप में अपदस्थ कर नजरबंद कर रखा गया था।
- 2005 पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने नियंत्रण रेखा को भूकंप राहत कार्य के लिए खोलने का सुझाव दिया था।
- 2007 आठ वर्ष के बाद बेनजिर भुट्टो अपने वतन पाकिस्तान लौटी थी।
- 2008 मायावती ने रायबरेली की रेल कोच फैक्ट्री के लिए 189.25 करोड़ एकड़ भूमि रेल मंत्रालय को वापस की थी।
- 2012 सीरिया ने मारते अल नुमाम में सैन्य हवाई हमले किये जिसमें 40 लोग मारे गये थे।

यूपी चुनाव: अयोध्या, गोरखपुर और संभल में आखिर क्यों दी जा रही है चुनौती?

सौरभ वार्धप्य

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के साथ ही प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और चुनौती देने का दौर तेज हो गया है। अयोध्या, गोरखपुर और संभल जैसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्रों के नाम लेकर नेताओं के बीच सीधी चुनावी टक्कर की बात की जा रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच अयोध्या से चुनाव लड़ने को लेकर शुरू हुई जुबानी जंग में अब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी अपनी चुनौती जोड़ दी है। उन्होंने योगी आदित्यनाथ को संभल और अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती दी है। इस घटनाक्रम ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर इन तीन स्थानों को लेकर इतनी राजनीतिक गर्मी क्यों है?

दरअसल, यह केवल तीन विधानसभा क्षेत्रों का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे धार्मिक प्रतीक, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक समीकरण और सत्ता के प्रति जनता के रुख को समझने की कोशिश भी दिखाई देती है। इन चुनौतियों के माध्यम से राजनीतिक दल अपने विरोधियों को उनके स्थापित प्रभाव क्षेत्रों से बाहर निकालकर जनता का सामना करने के लिए कह रहे हैं।

अयोध्या का नाम आते ही राम मंदिर, धार्मिक आस्था और भारतीय राजनीति में उसके प्रभाव की चर्चा स्वाभाविक है। पिछले कुछ वर्षों में अयोध्या में बड़े पैमाने पर विकास परियोजनाएं शुरू हुई हैं। सड़कें, परिवहन सुविधाएं, पर्यटन और धार्मिक गतिविधियां से जुड़ा बुनियादी ढांचा राजनीतिक विचशं का प्रमुख हिस्सा बना है। भारतीय जनता पार्टी के लिए अयोध्या धार्मिक आस्था और विकास के दावों को प्रस्तुत करने का महत्वपूर्ण केंद्र रही है।

महाराष्ट्र महागठबंधन और महाविकास आघाड़ी

अमिताभ श्रीवास्तव

महाराष्ट्र में किसी भी राजनीतिक गतिविधि में असहमति के बाद सहमति बनने की एक परंपरा बन चुकी है। राज्य में महागठबंधन और महाविकास आघाड़ी आए दिन किसी आपसी विवाद को लेकर भिड़ते और सिमटते देखे जाते हैं। यद्यपि जैसे ही उनकी एकजुटता पर उंगली उठती है, वैसे ही आपस में मिलकर उनकी मुट्ठी बंध जाती है। लोकसभा, विधानसभा, स्थानीय निकाय जैसे अनेक स्तरों के चुनाव होने के बावजूद कोई भी दल अपनी सीमाओं को समझने के लिए तैयार नहीं है। वह मानता है कि दबाव से मोलभाव और अस्तित्व का संकट खड़ा नहीं होगा। किसी सीमा तक गठबंधन धर्म में सुनवाई और कुछ पा लेने से परिदृश्य मनमर्जी का दिख जाता है। किंतु वास्तविकता का धरातल वैसा नहीं होता। जिस हक की लड़ाई लड़ी जाती है, उसमें किसी सहयोग के साथ जीत रूपजा ने सीट अपने पास रखी। वह न शक्ति प्रदर्शन होती है और न ही किसी क्षमता का प्रदर्शन मानी जा सकती है। यदि वह सब सच है भी तो राजनीतिक धमकियों के बाद असल स्थिति कभी-कहीं किसी स्थान पर परख लेना चाहिए। ताजा मामलों में राज्य विधान परिषद चुनाव को लेकर महागठबंधन के भीतर मतभेद दिख रहे हैं। पुणे शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) के उम्मीदवार कौस्तुभ गावडे के बजाय मंत्री उदय सावंत के ओएसडी और निर्दलीय उम्मीदवार सचिन सानप को समर्थन देने की घोषणा की है। दरअसल, पुणे शिक्षक सीट पर शिवसेना अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन भाजपा ने सीट अपने पास रखी। इसके बाद शिंदे ने अपने करीबी मंगेश चिवटे को एबी फॉर्म देकर चुनाव मैदान में उतारने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्हें अपना नामांकन वापस लेना पड़ा। अब शिवसेना की शिंदे गुट उनके प्रचार अभियान में भी शामिल रहेगा। उपर, अमरावती में शिवसेना के उम्मीदवार के सामने भाजपा का बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में है, जबकि बंटवारे में

लेकिन वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद की जीत ने यह स्पष्ट किया कि धार्मिक महत्व और चुनावी परिणामों के बीच सीधा तथा सुनिश्चित संबंध मान लेना उचित नहीं है। अयोध्या विधानसभा क्षेत्र में भाजपा को बढ़त जरूर मिली थी, लेकिन फैजाबाद लोकसभा सीट का परिणाम विपक्ष के लिए राजनीतिक उत्साह का कारण बना।

इसी पृष्ठभूमि में अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अयोध्या से चुनाव लड़ने की चुनौती दी। जवाब में योगी ने भी अखिलेश यादव को वहीं से उनके सामने चुनावी मैदान में उतरने की चुनौती दे दी। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच इस तरह की बयानबाजी को वास्तविक उम्मीदवारी की घोषणा नहीं माना जाना चाहिए।

अयोध्या की राजनीति में अब यह सवाल भी महत्वपूर्ण है कि बड़े विकास कार्यों के साथ स्थानीय नागरिकों को कितनी सुविधाएं मिली हैं। जल निकासी, सड़क निर्माण, व्यापारियों की समस्याएं, जमीन की कीमतों में बदलाव और स्थानीय लोगों की जरूरतें भी चुनावी बहस के हिस्से हैं। मंदिर और आस्था का महत्व अपनी जगह है, लेकिन मतदाता अपने दैनिक जीवन से जुड़े सवालों का उत्तर भी चाहते हैं।

गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक पहचान से गहराई से जुड़ा क्षेत्र है। यहां गोरक्षपीठ का सामाजिक और धार्मिक प्रभाव भी राजनीति को प्रभावित करता है। योगी आदित्यनाथ लंबे समय तक गोरखपुर से सांसद रहे और वर्तमान में गोरखपुर शहरी विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में गोरखपुर का नाम लेकर अखिलेश यादव को चुनाव लड़ने की चुनौती देना राजनीतिक प्रतीकवाद से जुड़ा कदम है।

विचार



ओवैसी ने अखिलेश यादव को गोरखपुर से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी के राजनीतिक प्रभाव और उसके सामाजिक आधार पर सवाल उठाए हैं। उनके बयान का उद्देश्य विपक्षी राजनीति में अपनी जगह बनाना और सपा के दावों को चुनौती देना भी समझा जा सकता है। गोरखपुर में विकास, स्वास्थ्य सेवाएं, रोजगार, शिक्षा, औद्योगिक गतिविधियां और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याएं चुनावी चर्चा के अहम विषय हो सकते हैं। मुख्यमंत्री के गृह क्षेत्र के रूप में इसकी राजनीतिक संवेदनशीलता अधिक है, लेकिन किसी नेता की लोकप्रियता का आकलन केवल चुनौती स्वीकार करने या न करने से नहीं किया जा सकता। इसके लिए जनता के बीच उसके काम, नीतियों और स्थानीय मुद्दों पर प्रदर्शन का मूल्यांकन जरूरी है।

संभल उत्तर प्रदेश की राजनीति में इसलिए भी चर्चा के केंद्र में है, क्योंकि यहां धार्मिक स्थलों, सामुदायिक संबंधों और कानून-व्यवस्था से जुड़े मुद्दों पर लगातार राजनीतिक बहस होती रही है। नवंबर 2024 में शाही जामा मस्जिद के सर्वेक्षण को लेकर हुई हिंसा के बाद यह क्षेत्र भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच आरोप-प्रत्यारोप का प्रमुख केंद्र बन गया। अगस्त 2026 में विधानसभा में पेश न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने भी इस विवाद को राजनीतिक बहस में बनाए रखा है। रिपोर्ट के

मध्य प्रदेश में मामा बनाम मुख्यमंत्री की जंग तेज!

नीरज कुमार दुबे

मध्य प्रदेश की सियासत में इन दिनों फिर वही पुराना सवाल फिर उठाने लगा है कि क्या सूबे की राजनीति में शिवराज सिंह चौहान का दखल अब भी उतना ही हमदार है, या मुख्यमंत्री मोहन यादव अपनी अलग लकीर खींचने में जुटे हैं? ऊपर से सब कुछ भाजपा के अनुशासित कुन्बे जैसा दिखता है, लेकिन बुधनी के कोसमी गांव से लेकर किसानों की मूंछ खरीदी और लाड़ली बहना योजना तक, कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं, जिन्होंने भोपाल के सियासी गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

उल्लेखनीय है कि ताजा चिंगारी सीहोर जिले के कोसमी गांव से उठी है। यह वही इलाका है, जहां शिवराज सिंह चौहान की बरसों पुरानी राजनीतिक जमीन रही है। गांव में आदिवासी परिवारों के मकान हटाए जाने, फसलों को नुकसान पहुंचने और कुओं को मिट्टी से भरने की शिकायतों पर शिवराज ने अपनी ही पार्टी की सरकार के अधिकारियों को कठघरे में खड़ा कर दिया। उनका रुख साफ था कि सरकार किसी की भी हो, गरीब और आदिवासी परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की और मोहन यादव से बात करने की बात कही।

देखा जाये तो राजनीति में बात सिर्फ इतनी नहीं है कि किसी गांव में मकान टूटे और एक नेता ने नाराजगी जता दी। सवाल यह है कि शिवराज ने यह आवाज उस समान नहीं रहे। साफ था कि गठबंधन की मजबूती से मतों के बंटवारे को बचाकर विधानसभा चुनाव जीत लिया गया, लेकिन स्थानीय स्तर पर होने वाले चुनावों में सभी दलों को फूट के बाद अपना आधार जांचना जरूरी हो गया था।

निष्कर्षों और विभिन्न दलों के आरोपों को उनके संबंधित स्रोतों के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। ओवैसी ने योगी आदित्यनाथ को संभल से चुनाव लड़ने की चुनौती देते हुए वहां की घटनाओं और प्रशासनिक कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। इस चुनौती के पीछे यह राजनीतिक संदेश भी है कि सत्ता में बैठे नेताओं को उन क्षेत्रों में जाकर जनता का सामना करना चाहिए, जहां उनकी नीतियों और प्रशासनिक फैसलों पर गंभीर सवाल उठते हैं।

हालांकि, संभल की राजनीति को केवल धार्मिक पहचान तक सीमित करना उचित नहीं होगा। यहां रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कारोबार, सड़क, बिजली और कानून के निष्पक्ष पालन जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण हैं। लोकतंत्र में किसी भी समुदाय की सुरक्षा, नागरिक अधिकारों और कानून के समान अनुपालन को चुनावी लाभ-हानि से ऊपर रखा जाना चाहिए।

अयोध्या, गोरखपुर और संभल को लेकर जारी चुनौतीपूर्ण बयानबाजी से राजनीतिक दलों को सुखियां जरूर मिल सकती हैं, लेकिन चुनाव का वास्तविक अर्थ इससे कहीं व्यापक है। प्रदेश के युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य चाहिए, व्यापारियों को स्थिर और भरोसेमंद व्यवस्था चाहिए तथा आम नागरिकों को बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और सुरक्षित वातावरण चाहिए।

उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में चुनावी चर्चा केवल इस प्रश्न तक सीमित नहीं रह सकती कि कौन-सा बड़ा नेता किस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेगा। यह भी पूछा जाना चाहिए कि पिछले कार्यकाल में कितने रोजगार के अवसर बने, सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता में कितना सुधार हुआ, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच सुविधाओं

का अंतर कितना कम हुआ और भ्रष्टाचार तथा प्रशासनिक जवाबदेही पर क्या प्रगति हुई।

इसी तरह विपक्ष की जिम्मेदारी भी केवल सरकार को चुनौती देने तक सीमित नहीं है। उसे अपनी नीतियों, उम्मीदवारों, सामाजिक प्रतिनिधित्व और विकास संबंधी योजनाओं का स्पष्ट खाका जनता के सामने रखना होगा। भाजपा, समाजवादी पार्टी और एआईएमआईएम सहित सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा है कि वे आरोपों के साथ ठोस तथ्य और अपने वैकल्पिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत करें। अयोध्या, गोरखपुर और संभल की राजनीतिक अहमियत अलग-अलग हैं, लेकिन तीनों जगह एक समान सवाल सामने आता है क्या राजनीति जनता की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित रहेगी या चुनावी मुकाबला मुख्य रूप से प्रतीकात्मक चुनौतियों और आरोप-प्रत्यारोप तक सिमट जाएगा ?

योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और असदुद्दीन ओवैसी के बीच जारी बयानबाजी को इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझने की जरूरत है। किसी नेता का राजनीतिक साहस केवल विरोधी के गढ़ में चुनाव लड़ने से नहीं, बल्कि जनता के सवालों का जवाब देने, अपने वादों का हिसाब प्रस्तुत करने और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने से भी परखा जाता है।

आखिरकार, चुनाव किसी नेता की प्रतिष्ठा का निजी मुकाबला नहीं, बल्कि जनता के भविष्य का फैसला है। मतदाता को यह अधिकार है कि वह धार्मिक और राजनीतिक नारों से आगे बढ़कर विकास, रोजगार, सामाजिक सद्भाव, कानून-व्यवस्था और जनकल्याण के आधार पर सवाल पूछे। अयोध्या की आस्था, गोरखपुर की राजनीतिक विरासत और संभल की संवेदनशीलता तीनों का सम्मान तभी सार्थक होगा, जब राजनीति का केंद्र आम नागरिक और उसकी समस्याएं बनें।



आवास तथा भोजन की व्यवस्था करने की बात कही। दूसरी तरफ, कलेक्टर की रिपोर्ट में वन भूमि पर अतिक्रमण और सामौन के पौधों को नुकसान पहुंचाने के आरोप सामने आए। यानी मामला केवल सियासी बयानबाजी का नहीं, बल्कि वन संरक्षण, प्रशासनिक कार्रवाई और आदिवासी परिवारों के अधिकारों का भी है।

लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में हर घटना का एक स्थानीय और एक राजनीतिक अर्थ होता है। कोसमी का मामला इसलिए भी चर्चा में है, क्योंकि शिवराज ने जिस इलाके में लंबे समय तक अपनी राजनीतिक पकड़ बनाई, वहीं की घटना पर उनका इस तरह सामने आना कई सवाल खड़े करता है। सवाल उठ रहा है कि क्या यह केवल अपने पुराने मतदाताओं के प्रति जवाबदेही है, या इसके पीछे भोपाल की सत्ता के साथ तालमेल का कोई बड़ा सवाल भी छिपा है ?

इस कहानी का दूसरा सिरा लाड़ली बहना योजना से भी जुड़ता है। शिवराज की राजनीति की पहचान बनी इस योजना ने प्रदेश में महिलाओं के बीच उनकी अलग छवि बनाई। अब मुख्यमंत्री मोहन यादव की ओर से योजना के खर्च को भारी बताने वाली टिप्पणी ने पुरानी राजनीतिक विरासत और मौजूदा सरकार की आर्थिक

कुर्सी की लड़ाई मान लेना जल्दबाजी होगी। भाजपा में संघटन का अपना अनुशासन और केंद्रीय नेतृत्व की भूमिका है। अभी तक सामने आई घटनाएं प्रशासन, किसान नीति और राजनीतिक विरासत पर मनबंद दिखाती हैं। मगर वे किसी औपचारिक सत्ता-संघर्ष को साबित नहीं करती।

फिलहाल मध्य प्रदेश की राजनीति का असली इम्तिहान बयानों से आगे होगा। कोसमी की जांच में क्या कार्रवाई होती है, प्रभावित परिवारों को क्या राहत मिलती है, लाड़ली बहना योजना को लेकर राज्य सरकार क्या फैसला करती है और किसानों की खरीदी व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती है, इन सवालों के जवाब ही आगे की तस्वीर साफ करेें।

बहरहाल, भोपाल की सियासत में मामा शिवराज की हुंकार अब भी गूंज रही है, तो मुख्यमंत्री मोहन यादव भी अपने फैसलों से सत्ता पर अपनी पकड़ और नेतृत्व की लकीर खींचने में जुटे हैं। दोनों के बीच सियासी खिंचाव की आहट साफ सुनाई दे रही है, लेकिन इसे खुली जंग का नाम देना अभी जल्दबाजी होगी। असली तस्वीर तब खुलेगी जब यह सामने आये कि कोसमी के मामले में सरकार के कदम क्या होते हैं, लाड़ली बहना योजना पर क्या रुख अपनایा जाता है और किसानों के सवाल पर किसका पलड़ा भारी पड़ता है। क्योंकि मध्य प्रदेश की राजनीति में सियासी इरादे सिर्फ बयानों से जाहिर नहीं होते, उनका असली रंग फैसलों में दिखता है। भोपाल में फिलहाल बयान गूंज रहे हैं, लेकिन निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि अगली चाल कौन चलता है और बाजी किस करवट बैठती है ?

अपने आचरण से देश की सर्वाधिक किरकिरी करा रहे डोनाल्ड ट्रम्प?

राजेश बादल

दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क के लोग इन दिनों हक्का-बक्का हैं। उनका धर्मसंकट यह है कि वे संसार के सबसे विकसित, धनवान और आधुनिक राष्ट्र की कमान ऐसे व्यक्ति को कब तक दे सकते हैं, जिसके लिए न कोई नीतियां मायने रखती हैं, न लोकतांत्रिक मूल्य और न अंतरराष्ट्रीय मर्यादाएं। अमेरिकी इतिहास में डोनाल्ड ट्रम्प संभवतया ऐसे पहले राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने अपने आचरण से देश की सर्वाधिक किरकिरी कराई है। वे कब कौन सा फैसला लेंगे, कोई नहीं जानता। अब उन्होंने जो निर्णय लिया है, वह अमेरिकावासियों को ही नहीं, समूचे विश्व को हैरान कर रहा है।

यूटर्न के लिए उपहास की सीमा तक जाने वाले राष्ट्रपति अब कह रहे हैं कि वे रूस से अपने देश के लिए 1८ लाख टन से अधिक डीजल खरीदेंगे। तीन किस्तों में रूसअमेरिका को यह डीजल देगा। ट्रम्प के ऐसा करने की वजह साफ है। वे आगामी मध्यावधि चुनाव में अत्यंत कमजोर स्थिति में हैं। सनक रहे फैसलों ने उन्हें अपने ही देश में बेहद अपमानजनक परिस्थितियों में पहुंचा दिया है।

तामाम देशों के साथ-साथ वे अमेरिकी मतदाता भी पिछ्न और निराश हैं, जिन्होंने उन्हें दूसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए अपना वोट दिया था। जब से ट्रम्प दोबारा राष्ट्रपति बने हैं, अमेरिका की हालत बहुत खराब हो चुकी है। आर्थिक मोर्चे पर और अंतरराष्ट्रीय साख के मामले में अमेरिका पहले जैसा नहीं रहा। बेरोजगारी चरम पर है, उत्पादन बढ़ नहीं रहा है, स्वास्थ्य सेवाएं लचर हुई हैं, डीजल की कीमतें लगभग दू गुनी हो चुकी हैं। महंगाई आसमान पर है। लेकिन ट्रम्प मध्यावधि चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडा अपना रहे हैं।

चंद रोज पहले ही उन्होंने भारत और चीन समेत अनेक राष्ट्रों पर 100 फीसदी भारी जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था। इसका कानून भी वहां अस्तित्व में आ चुका है। मगर अब अमेरिका के निच विभाग ने एक अस्थायी फरमान जारी किया है। इसमें कहा गया है कि अगले साल अप्रैल



तक अमेरिका रूस से डीजल आयात कर सकता है।

बाकायदा डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बारे में रूस के राष्ट्रपति के साथ फटाफट समझौता भी कर डाला है। ट्रम्प ने अपनी टिप्पणी में लिखा कि “अभी रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ बहुत सफल बातचीत पूरी की है। इसमें तय हुआ है कि रूस तुरंत अमेरिकी मार्केट तथा पश्चिमी देशों के बाजार को तीन लाख टन से ज्यादा डीजल फ्यूल सप्लाई करेगा।

नवंबर के महीने में पांच लाख टन और सप्लाई करेगा। उसके तुरंत बाद 10 लाख टन और आपूर्ति करेगा। इसके बाद अपनी डीजल रिफाइनरियों की स्थिति के आधार पर रूस 30 लाख टन डीजल और अमेरिका को देगा। असल में ईरान जंग के चलते अमेरिका में ट्रंक परिवहन का कारोबार लगभग टप सा हो गया है। वहां साठ से अस्सी फीसदी माल दुलाई ट्रकों से ही होती है।

डीजल संकट कितना गंभीर है, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है कि ट्रम्प सरकार कच्चा तेल आयात नहीं कर रही है। वह परिकृत डीजल ही ले रही है, जिससे अमेरिका में रिफाइनरियों से कच्चे तेल को डीजल में बदलने का समय बच जाए। चुनाव सिर पर हैं, इसलिए ट्रम्प की घबराहट समझी जा सकती है।

खुद यूक्रेन भी अमेरिका के इस रवैये से हैरान है। अब डोनाल्ड ट्रम्प के इस निर्णय के बाद उसने कहा है कि रूस को अमेरिका से जो धन मिलेगा, उसका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ किया जाएगा। वह खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका-रूस के समझौते को पुतिन के लिए उपहार बताया है, जो शांति के बजाय युद्ध को और बढ़ावा देगा। यूक्रेन का साफ कहना है कि रूस से

धर्मांतरण,जाति और आरक्षण का महासंग्राम!

किशन समुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत में धर्म की स्वतंत्रता, सामाजिक न्याय और आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के बीच लंबे समय से चल रही बहस ने 15 अक्टूबर 2026 को एक महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया।उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की याचिका खारिज करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा,जिसमें इस्लाम अपनाते वाले व्यक्तियों को उनके पुराने जातिगत या सामाजिक वर्ग के आधार पर स्वतःपिछड़ा वर्ग (मुस्लिम)का आरक्षण देने संबंधी सरकारी आदेश को असंवैधानिक ठहराया गया था। मैं मानता हूँ कि इस फैसले का मूल संदेश यह है कि सिर्फ धर्म परिवर्तन कर लेने से व्यक्ति अपनी पुरानी जाति या सामाजिक श्रेणी के आधार पर किसी दूसरी अधिसूचित पिछड़ी मुस्लिम समुदाय-श्रेणी का सदस्य नहीं बन जाता हालाँकि, इस फैसले को यह कहकर समझना भी सही नहीं होगा कि भारत में किसी भी धर्म के व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में पिछड़े वर्ग का आरक्षण नहीं मिल सकता। वास्तविक प्रश्न यह है कि संबंथित समुदाय को कानून के तहत मान्यता प्राप्त है या नहीं और आरक्षण का दावा निर्धारित संवैधानिक एवं कानूनी शर्तों को पूरा करता है या नहीं। इस महत्वपूर्ण मामले का नाम द सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट वरसेंस.समीर अहमद एंड ऑर्दर्स है। उच्चतम न्यायालय में यह विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 25507/2026 के रूप में दर्ज हुई। याचिकाकर्ता तमिलनाडु सरकार थी और मामला समीर अहमद एन सहित अन्य पक्षकारों से संबंधित था। उच्चतम न्यायालय ने 15 अक्टूबर 2026 को राज्य सरकार की चुनौती खारिज कर दी। इस विवाद की जड़ मद्रास उच्च न्यायालय की मद्रुई पीठ का 25 जून 2026 का निर्णय था। मामला रिट याचिका संख्या डब्लू.पी.(एमडी) नों . 7127 श्रद्ध 2022, समीर

अहमद एन बराम जिला कलेक्टर, तूतीकोरिन जिला,से संबंधित था। उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार के 9 मार्च 2024 के सरकारी आदेश को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। इसके बाद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की,जिसे अब सटीकता से खारिज कर दिया गया है। साथियों बात अगर हम तमिलनाडु सरकार ने आखिर कौन-सा आदेश जारी किया था ?

इसको समझने की करें तो इस पूरे विवाद का केंद्र तमिलनाडु सरकार के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का जी.ओ.(एमएस.)नों 31, दिनांक 9 मार्च 2024 था। सरकार ने तमिलनाडु पिछड़ा वर्ग आयोग की 6 फरवरी 2024 की सिफारिश के आधार पर यह व्यवस्था की थी कि पिछड़ा वर्ग,अति पिछड़ा वर्ग, विमुक्त समुदायों अथवा अनुसूचित जातियों से संबंधित व्यक्ति यदिइस्लाम अपना लेते हैं, तो उन्हें राज्य की सात अधिसूचित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय-श्रेणियों में से किसी एक के अंतर्गत प्रमाणपत्र देकर आरक्षण का लाभ लेने की अनुमति दी जा सके।सरकार का तर्क था कि जो लोग पहले से आरक्षण का लाभ प्राप्त कर रहे थे, उन्हें केवल धर्म परिवर्तन के कारण उस सुविधा से वंचित नहीं होना चाहिए।लेकिन कानूनी विवाद इस बात पर उठा कि क्या सरकार एक प्रशासनिक आदेश के माध्यम से किसी व्यक्ति को ऐसे मुस्लिम समुदाय का सदस्य घोषित कर सकती है, जिससे उसका वास्तविक सामाजिक या सामुदायिक संबंध स्थापित नहीं है।

साथियों बात अगर हम सात मुस्लिम पिछड़ा वर्ग श्रेणियों पर फैसले के दूरगामी परिणाम को समझने की करें तो तमिलनाडु में सात अधिसूचित पिछड़ा वर्ग मुस्लिम समुदाय हैं,अंसार, दक्कन मुस्लिम,डुबेकुला, लब्बाई (रौथर और मरकायर सहित),मापिला,शेख और सैयद। इन समुदायों की मान्यता राज्य के आरक्षण कानून के अंतर्गत है।

मां बेटी का रिश्ता दुनिया में सबसे अनमोल होता है। बेटी को मां की ही छवि माना जाता है क्योंकि वो उन्हीं से सारे गुण व आदतें सीखती हैं। साथ ही एक मां में बेटी अपना दोस्त, हमदर्द भी ढूंढ लेती हैं। वहीं, बेटी के रूप में एक मां अपना बचपन दोबारा जी लेती हैं। मगर, कई बार मां-बेटी के रिश्ते में जरा-सी नौक-झोंक भी हो जाती है जो धीरे-धीरे उनके बीच दूरियां बढ़ा देती हैं। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में आज हम आपको बताएंगे।

उम्र के पहले जिम्मेदारियों का अहसास

अक्सर माएं अपनी बेटियों को बचपन से ही जिम्मेदारियों का अहसास करवाने लगती हैं। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि उन्हें दूसरे घर जाना है इसलिए काम करो। इसके कारण बच्चियां अपना बचपन खो देती हैं और मां से दूरी भी बना लेती हैं।

बेटी पर विश्वास न करना

अगर बेटी मां-पिता की इज्जत का खयाल रख रही हैं तो जाहिर है वो आपसे भरोसे की उम्मीद भी रखेगी। बेटियाँ भी चाहती हैं कि घर के लोग उन पर भरोसा करें मगर, जब आप, खासकर मां और एक औरत होकर जब आप अपनी बेटी पर विश्वास नहीं करती तो उनका मनोबल टूट जाता है। इसके कारण वो आपसे कटी-कटी रहने लगती हैं। और ये एक बहुत अहम् वजह है कि बेटियाँ अपनी माँ से दूर हो जाती हैं।

रोक-टोक करना

वेशक बेटी को सही गलत का एहसास करवाना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है लेकिन कई आपकी चिंता इतना ओवरप्रोजेक्टिव हो जाती है कि लड़कियां इन्हें बाउंडेशन समझ लेती हैं। अब अगर कोई बेटियों के मन की बात ना समझ पाए तो दूरियां जायज है।

अगर आप भी अपने बच्चे की कम हाइट से हैं परेशान तो उन्हें

रोजाना कराएं ये आसन



बच्चे खाने के मामले में बहुत आनाकानी करते हैं। मगर इससे उनके शारीरिक व मानसिक विकास में रुकावटें आने लगती हैं। इसके अलावा कई बच्चों की हाइट भी कम रह जाती है। मगर असल में, हाइट यह एक उम्र के बाद बढ़ने बंद हो जाती है। ऐसे में कई पेरेंट्स इसके डर के कारण बच्चों को हाइट बढ़ाने की दवाइयां खिलाने लगते हैं। मगर इससे सेहत के खराब होने की परेशानी हो सकती है। ऐसे में आप चाहे तो बच्चे की डेली रूटीन में योगासन को जोड़ सकते हैं। इसे करने में बॉडी की अच्छे से स्ट्रेचिंग होती है। ऐसे में बच्चे की नेचुरल तरीके से हाइट बढ़ने के साथ सेहत दुरुस्त रहने में भी मदद मिलेगा।

ताड़ासन

- 1. सबसे पहले खुली जगह पर एकदम सीधे खड़े हो जाएं।
- 2. दोनों हाथों की उंगलियों को बीच में फंसाकर या हाथों को नमस्कार की मुद्रा में रख कर ऊपर की तरह करें।
- 3. धीरे-धीरे एंड्रियों को उठाकर शरीर का सारा भार पंजों पर डालें।
- 4. इसी मुद्रा में खड़े रहकर पूरे शरीर को स्ट्रेच करें।
- 5. फिर गहरी सांस लें।
- 6. थोड़ी देर बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं।

- 7. इस आसन को 4-5 बार करें। इससे हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी। पूरे शरीर में मजबूती आएगी।

वृक्षासन

- 1. इस आसन को करने के लिए, खुली जगह पर सीधे खड़े हो जाएं।
 - 2. दाहिने पैर को अपने बाएं पैर पर रखें।
 - 3. दोनों हाथों को नमस्ते की मुद्रा में रखकर ऊपर ले जाएं।
 - 4. एक पैर से बैलेंस बनाएं।
 - 5. थोड़ी देर इसी मुद्रा में रहने के बाद सामान्य अवस्था में आ जाएं।
 - 6. इसके बाद दूसरे पैर से इस योगासन को करें।
- इससे रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी होगी। पैरों व हाथों की मांसपेशियों में खिंचाव होने से हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी।



योगासन करने के अन्य लाभ

- पूरे शरीर में खिंचाव होने से मांसपेशियों व हड्डियों में मजबूती आएगी।
- पाचन तंत्र दुरुस्त होकर पेट संबंधी समस्याएं दूर होगी।
- दिमाग शांत होने से स्मरण शक्ति बढ़ेगी।
- कमजोरी, थकान व आलस दूर होकर दिनभर तरोताजा महसूस होगा।
- शरीर में खून का संचार बेहतर होने में मदद मिलेगी।
- इम्यूनिटी बूस्ट होने से मौसमी व अन्य बीमारियों से बचाव रहेगा।



बच्चों के बेहतर शारीरिक विकास के लिए उनकी डाइट खास होनी चाहिए। खासतौर पर उनकी मांसपेशियों व हड्डियों की मजबूती के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है। इसकी कमी से उनकी हड्डियां कमजोर होने के साथ शारीरिक विकास धीमा पड़ जाता है। वैसे तो इसकी कमी को पूरा करने के लिए सूरज की रोशनी बेहद फायदेमंद होती है। यह शरीर में कैल्शियम को अवशोषित करने व हड्डियों में मजबूती दिलाने में मदद करता है। मगर आप डाइट में कुछ चीजों को शामिल करके भी इसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए आज हम विटामिन-डी से भरपूर चीजों के बारे में बताते हैं। मगर उससे पहले जानते हैं इसकी कमी के लक्षण....

बच्चे में पहचाने विटामिन डी की कमी, जरूर खिलाएं यह आहार

बच्चे में विटामिन डी की कमी के लक्षण

- मांसपेशियों व हड्डियों का कमजोर होकर दर्द होना
- शारीरिक विकास धीमी गति से चलना
- स्वभाव में चिड़चिड़ापन बढ़ना
- इसकी कमी के कारण बच्चे को रिकरेंट इन्फेक्शन यानी बार-बार सर्दी-खांसी व मौसमी बीमारियां होना
- दिनभर थकान व कमजोरी रहना

विटामिन डी से भरपूर सुपर फूड्स

सोया से भरपूर चीजें

विटामिन डी से भरपूर चीजों की लिस्ट में सोया भी शामिल होता है। ऐसे में बच्चे की डाइट में सोया से

भरपूर टोफू, दूध और सोयाबीन शामिल करें। इससे बच्चे को सही मात्रा में विटामिन डी मिलने के साथ शारीरिक व मानसिक विकास होने में मदद मिलेगी।

दूध : इसकी कमी पूरा करने के लिए दूध पीना भी बेस्ट ऑप्शन है। असल में दूध में कैल्शियम के साथ उचित मात्रा में विटामिन डी में पाया जाता है। इसलिए रोजाना 1 गिलास दूध का सेवन करने से बच्चे में इसकी कमी पूरी की जा सकती है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, 1 गिलास दूध का सेवन करने से दिनभर की जरूरत के अनुसार 1/4 विटामिन डी की मिल सकता है।

संतरा : वैसे तो विटामिन-सी के लिए संतरा खाने की सलाह दी जाती है। मगर असल में, इसमें विटामिन-सी और डी सही मात्रा में मौजूद होता है। ऐसे में रोजाना इसका सेवन करने से विटामिन डी की सही मात्रा में मिलता है।

एक्सपर्ट्स के अनुसार, रोजाना 1 गिलास ताजे संतरे का जूस



कहीं बिगड़ तो नहीं रहा आपका बच्चा, कुछ इस तरह से पहचाने

बच्चे का मन कोरे कागज की तरह होता है। ऐसे में वे अपने आसपास के लोगों व चीजों जल्दी समझकर उन्हें सीख लेते हैं। कई बार वे ऐसी बातें व काम भी सीख लेते हैं जो उनके बेहतर मानसिक व व्यावहारिक विकास में बांधा डालते हैं। असल में, पेरेंट्स के बिजी होने या बच्चों को अधिक छूट देने से वे बिगड़ सकते हैं। ऐसे में कई बच्चे तो लड़ाई, मारपीट, गलत भाषा इस्तेमाल करना आदि शुरू कर देते हैं। ऐसे में पेरेंट्स का फर्ज बनता है कि वे शुरूआती दौर पर ही बच्चों पर ध्यान दें। तो चलिए आज हम आपको इस आर्टिकल में कुछ बातें बताते हैं, जो बच्चे के बिगड़ने की ओर इशारा करते हैं। ऐसे में आप समय रहते ही उनपर काबू पा सकते हैं।



दूसरों को तंग करना

छोटे बच्चे दूसरों को चिढ़ाकर खुश होते हैं। मगर बार-बार ऐसा बर्ताव करना सही नहीं होता है। ऐसे में उसकी संगत को पहचान कर उसे ऐसा करने से रोके। उसे सही व गलत की पहचान करवाते हुए एक बेहतर ईसान बनाएं।

लड़ाई करना

बच्चे का घर पर या पड़ोस में लड़ना भी उसके बिगड़ने की ओर इशारा करता है। असल में, ऐसी चीजें बच्चा घर के बड़े, दोस्तों व टीवी देखकर सीखता है। ऐसे में अपने घर

का माहौल शांत व खुशनुमा रखें। साथ ही उसके द्वारा मारपीट या झगड़ा करने पर उसे प्यार से गलती का अहसास करवाएं। कई बच्चे अटेंशन डेफिसिट हाइपर डिस्ऑर्डर के शिकार होने के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे में इस बात का खास ध्यान रखें।

गलत शब्दों व भाषा का इस्तेमाल करना

अगर कहीं आपका बच्चा गलत शब्द या भाषा का इस्तेमाल करें तो अलर्ट हो जाएं। इसका मतलब है कि वह बुरी संगत में पड़ रहा है। इसके लिए उसके कुछ गलत कहने पर तुरंत उसे रोके। मगर उसे डांटने की जगह प्यार से समझाएं। नहीं तो बच्चा नाराज हो सकता है। साथ ही घर का माहौल सही रखें। इसके अलावा इस बात ध्यान रखें कि आपका बच्चे किस से मिलता है। उसकी संगत चैक करके उसके बिगड़ने का कारण पता करें।

बात-बात पर जिद्द करना

अक्सर बच्चों को छोटी-छोटी बातों पर भी जिद्द करने की आदत होती है। मगर अगर कई बच्चा किसी बात पर अड़ जाएं, चंटों रोता रहे या खाना-पीना छोड़ दें तो यह उसके बिगड़ने की ओर इशारा करता है। ऐसे में मां-बाप का फर्ज है कि वे बच्चे को सही-गलत की पहचान करवाते हैं उसे सही राह पर लाएं। अगर बच्चा प्यार से ना माने तो इसके लिए सख्ती भी कर सकते हैं।

झूठ बोलना व चोरी करना

बच्चे का झूठ बोलना व चोरी करना भी उसके बिगड़ने की ओर संकेत करता है। ऐसे में उसका झूठ पकड़ कर प्यार से उसे समझाएं। बच्चे का मन बड़ा ही चंचल होता है। ऐसे में उसे डांटने की जगह प्यार से सही व गलत बताएं। साथ ही उससे ऐसा करने का कारण पूछें। इसके अलावा बच्चे की जरूरत का अच्छे से ध्यान रखें।



बेटी और बेटे में फर्क करना

समय भले ही बदल चुका हो लेकिन बेटी और बेटे के बीच आज भी दीवार खड़ी कर दी जाती है। इसके कारण बेटी के मन में हीनभावना जन्म ले लेती है और वो मानसिक तौर पर अलग हो जाती है।

मन की बात ना समझना

बेटियों को रोकना टोकना हर घर की बात है। और इसी रोक टोक की वजह से कई बार बेटियाँ अपनी माँ से दूर होती जाती हैं। बेटियों की मन की बात अगर माँ ही न समझ पाए तो ये दूरियां जायज है। इसलिए अत्यधिक रोक टोक पर बेटियां अपनी माँ से थोड़ी दूरी बना लेती हैं। अगर आप अपनी बेटी के साथ रिश्ता मजबूत बनाना चाहते हैं तो ये गलतियां ना दोहराएं। हर बेटी को घर में वो प्यार मिलना चाहिए जिसकी वो हकदार है।

कुछ साल पहले टेलीविजन मनोरंजन का एक मात्र जरिया था। लेकिन समय के साथ-साथ मनोरंजन के विकल्प बढ़ते गए। पहले बच्चे अपना अधिकतम समय कहानी सुन कर या खेल खुल कूद में बिताया करते हैं। परंतु आज वे टीवी देखते हुए अन्य कंप्यूटर खेल को खेल कर बिताना पसंद करते हैं। वे अपने शरीर को बिल्कुल भी हिलाना पसंद नहीं करते। कभी-कभी वे दवा के डर से समस्या को बताते ही नहीं हैं। परंतु माता-पिता होने के नाते उनके स्वास्थ्य का खयाल रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए साल में एक बार अपने बच्चे के पूरे शरीर की जांच कराना बहुत जरूरी है। यदि आपको लगता है कि आपके बच्चे की नजर कमजोर हो रही है। पता लगाने के लिए नीचे दिए गए लक्षणों पर ध्यान दें। यदि इनमें से कुछ लक्षण आपके बच्चे में मौजूद हैं तो तुरंत उसके आंखों की जांच कराएं।



बच्चों की नजर कमजोर होने के 10 लक्षणों को जानें

आंखों को मलना

बच्चों को नींद में अपनी आंखों को मलने की आदत होती है। लेकिन, अगर आपका बच्चा दिन भर आंखें मलता रहता है तो यह एक कमजोर नजर की निशानी हो सकती है।

सर दर्द

सर दर्द के कई कारण होते हैं। लेकिन अगर टीवी देखते हुए या पढ़ाई करते हुए उसे सर दर्द हो रहा है या रोज शाम को सर दर्द की शिकायत हो। तब समझ लें कि आपके बच्चे को चिकित्सा की आवश्यकता है।

एक आंख बंद करना

यदि आपका बच्चा एक आंख बंद करके टीवी देखने लगे या वीडियो गेम खेलने लगे तब समझ जाएं कि उसे चश्मा लगाने वाला है।

तेज रोशनी में पलक झपकना

क्या आपके बच्चे को उजाले से परेशानी होती है? या तेज रोशनी देखकर वह अपनी पलकों को तेजी से झपकता है? तेज रोशनी से धीमी रोशनी की ओर बढ़ते वक़्त क्या उसे धब्बे नजर आते हैं? इन सारे लक्षणों का कारण है विटामिन की कमी। अपने बच्चे के आहार में विटामिन ए की मात्रा को बढ़ाएं और उसे रोज सुबह



हैं। यदि ये मजाक ना हो कर हर दूसरे, तीसरे दिन की आदत बनती जा रही है तो आदत की वजह को पहचाने और अपने बच्चे की आंखों का इलाज कराएं।

सर घुमाना

बार-बार सर घुमाना भी कमजोर नजर का एक लक्षण है। यदि आपका बच्चा टीवी देखते वक़्त बीच-बीच में आंखों को बंद करके सर को हिलाता रहता है, तब इस लक्षण पर ध्यान दें।

नजदीक से देखना

यदि आपके बच्चे को दूर से कोई चीज साफ ना नजर आए और वो उसे देखने के लिए बहुत करीब आए। तब यह सरल लक्षण, उसकी कम होती दृष्टि का संकेतक है।

आई बॉल की गति

हालांकि, इस लक्षण को पहचानना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। इस लक्षण को पहचानने के लिए बात करते वक़्त आपको अपने बच्चे की आंखों को गौर से देखना होगा। यदि आई बॉल की गति में कुछ भिन्नता नजर आए तो तुरंत एक नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें।

लाल आंखें

नींद पूरी ना होना या नेत्रश्लेष्मला शोथ के कारण भी बच्चों की आंखें लाल हो सकती हैं। परंतु यदि ये दो कारण मौजूद ना हो तब कमजोर नजर ही इसका सही कारण होगा।

आंखों में दर्द

आंखों में दर्द के कारण बच्चे को आंखों में चुभन महसूस होती है तथा उसके आंखों से पानी भी आने लगता है। यदि ये लक्षण लगातार नजर आए तो समझे की निगाहों पर चश्मा टिकाने का वक़्त आ गया है।

गाजर का जूस पिराएं।

भंगापन

कई बार बच्चे मजाक में भी अपनी नजरों को तिरछा कर ते



पीने से बच्चे में विटामिन डी की कमी पूरी करने में मदद मिलती है। इसके अलावा संतरे अन्य पोषक तत्व व एंटी-ऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होता है। ऐसे में इसके सेवन से बच्चे की मांसपेशियों व हड्डियों में मजबूती आएगी। शारीरिक व मानसिक विकास बेहतर होने के साथ स्किन से जुड़ी परेशानियों से भी राहत रहेगी।

मशरूम : मशरूम खाने में टेस्टी होने के साथ विटामिन डी से भरपूर होती है। इसके सेवन से मांसपेशियों व हड्डियों में मजबूती आने में मदद मिलती है। खासतौर पर बच्चे की ग्रोथ के लिए मशरूम काफी फायदेमंद मानी जाती है। ऐसे में इसे बच्चे की डेली डाइट में जरूर शामिल करें। आप इससे बच्चे को अलग-अलग डिशेज बनाकर खिला सकते हैं।

अंडा : अगर आप नॉन वेजीटेरियन हैं तो बच्चे की डाइट में अंडे शामिल करें। इसका सफेद भाग विटामिन डी से भरपूर होता है। ऐसे में इसके सेवन से बच्चे को इसकी कमी पूरी करने में मदद मिलेगी। साथ ही उसकी सेहत में सुधार आएगा।

मोदी ओडिशा में आरबीआई डाटा सेंटर का 25 को करेंगे उद्घाटन

नईदिल्ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने के अंतिम सप्ताह में ओडिशा का दौरा कर सकते हैं। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी 25 अक्टूबर को खुर्दा जिले में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के नए डेटा सेंटर और प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करने के लिए ओडिशा जाएंगे। वहीं, राष्ट्रपति मुर्मू 28 अक्टूबर से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगी। दोनों के दौरे और कार्यक्रमों की तैयारियों की योजना बनाने के लिए यहां मुख्य सचिव अनु गंगों की अध्यक्षता में राज्यस्तरीय बैठक की जा रही है। राष्ट्रपति मुर्मू के संभावित कार्यक्रम के अनुसार, वह 28 अक्टूबर को ओडिशा पहुंचेंगी। मुर्मू इसके बाद रायरांपुर से बहलदा स्थित मां कीचकक्षरी मंदिर जाएंगी। उनके महलुडीहा स्थित लक्ष्मी मंडप और रायरांपुर में अपने आवास पर भी जाने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, दोनों के दौरों के दौरान कई आधिकारिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने की संभावना है।

परिसीमन प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक की मांग

मुंबई। शिवसेना नेता शायना एनसी ने शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रभामंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए उस पत्र का स्वागत किया, जिसमें परिसीमन प्रस्तावों पर सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की गई है। साथ ही, उन्होंने विपक्ष से संसदीय कार्यवाही में रचनात्मक रूप से भाग लेने का आग्रह किया। खड़गे की मांग पर प्रतिक्रिया देते हुए शायना एनसी ने कहा कि यह अच्छी बात है कि विपक्ष ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के साथ उनसे मिलने की इच्छा जताई है। लेकिन सच तो यह है कि जब संसद सत्र चल रहा होता है और मल्लिकार्जुन खड़गे को संसद के भीतर बैठकर चर्चा और बहस करनी चाहिए, तब वे वहां मौजूद नहीं होते, बल्कि संसद के बाहर विरोध-प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उन्होंने विपक्ष के नेताओं से संसदीय कार्यवाही में सकारात्मक रूप से हिस्सा लेने और महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा व बहस में शामिल होने का आग्रह किया।

दिपके की हिरासत को सीजेपी ने बताया गैरकानूनी

नईदिल्ली। काँकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की लीगल अफेयर्स हेड रत्ना सिंह, जो एक्टिविस्ट अभिजीत दिपके का पक्ष रख रही हैं, ने शनिवार को उनकी गिरफ्तारी को वैधता पर सवाल उठाया। उन्होंने स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट से दिपके को रिहा करने की अपील की और आरोप लगाया कि इस मामले में कानूनी प्रक्रिया और मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। एक्स (ट्विटर) पर एक पोस्ट में, रत्ना सिंह ने कहा कि दिपके ने केवल लोगों से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की अपील की थी। उन्होंने सवाल किया कि आखिर यह काम अपने आप में अपराध कैसे हो सकता है? उन्होंने लिखा कि स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट को अभिजीत दिपके को रिहा कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी गिरफ्तारी गैर-कानूनी है। उन्होंने बस लोगों से तिरंगा फहराने की अपील की थी। दिपके की हिरासत के हालात पर चिंता जताते हुए, रत्ना सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें उनके घर के बाहर से उठाया गया।

ध्रुव राठी के खिलाफ दिल्ली कोर्ट ने जारी किया जमानती वारंट

नईदिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के आईटी प्रकोष्ठ के एक सदस्य द्वारा 2018 में दायर मानहानि मामले में शनिवार को यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया। न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने विकास पांडे की ओर से दायर मामले में यह वारंट जारी किया जिन्होंने राठी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए गए एक वीडियो को लेकर उन पर मानहानि का आरोप लगाया है। अदालत के विस्तृत आदेश की प्रतीक्षा है। अदालत ने मामले में आगे की सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर की तारीख तय की है। यह घटनाक्रम अदालत द्वारा 12 अक्टूबर को राठी को नया समन जारी किए जाने के कुछ दिन बाद सामने आया है। उस समय अदालत ने कहा था कि शिकायतकर्ता पिछले कई वर्षों से राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। अदालत ने अपने आदेश में निर्देश दिया कि राठी के हरियाणा के गुरुग्राम स्थित आवास पर नया समन भेजा जाए।

पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त : सुखबीर सिंह बादल

चंडीगढ़। शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने शनिवार को मानसा में नशा-विरोधी कार्यकर्ता परविंदर सिंह उर्फ झोटा की हत्या के लिए सीधे तौर पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी की सरकार के कार्यकाल में राज्य की कानून-व्यवस्था की स्थिति बदतर हो गई है। राज्य सरकार द्वारा नशीले पदार्थों की समस्या और बढ़ते अपराधों से निपटने के तरीकों पर सवाल उठाते हुए, बादल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था को कभी प्राथमिकता नहीं दी और उनकी सरकार ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। बादल ने पत्रकारों से कहा कि हालात ऐसे हैं कि जैसे कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मुख्यमंत्री के पास इसके लिए समय ही नहीं है। इन पांच सालों में उन्होंने जीडीपी को सिर्फ अस्थायी तौर पर रखा है। मुख्यमंत्री खुद ऐशो-आराम में व्यस्त रहते हैं। वे खुद नशे में रहते हैं। यही वजह है कि हालात इतने खराब हो गए हैं। यह बहुत ही दयनीय स्थिति है।

भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने कांग्रेस को दी नसीहत

लोकतंत्र में चुनाव ही सरकार बदलने का वैध तरीका

नईदिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता राजीव चंद्रशेखर ने शनिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम की सत्ता परिवर्तन संबंधी टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता तब से ही ईमानदार नहीं रहे हैं, जब से उन्होंने 2जी स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों पर पर्दा डालने की कोशिश की थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कई पोस्ट के जरिए, चंद्रशेखर ने चिदंबरम पर 2त स्पेक्ट्रम और कोयला ब्लॉक आवंटन घोटालों को छिपाने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कांग्रेस के राजनीतिक दृष्टिकोण की आलोचना की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री के रूप में चिदंबरम के कार्यकाल का जिक्र करते हुए, कथित मार्क्सवादी-लेनिनवादी नक्सलियों के प्रति उनके कथित नरम रुख को भी याद किया।

चंद्रशेखर ने लिखा आपको सच बोले हुए काफी समय हो गया है। मैं आपको दोष नहीं दे सकता - ये हालात ही ऐसे हैं जिनमें आपको अपनी राजनीति करनी पड़ रही है। आप अब कांग्रेस में हैं। जिस समय से आपने अपने कार्यकाल में हुए 2त और कोयला ब्लॉक घोटालों तथा अन्य गलत कामों पर पर्दा डालने की कोशिश की, उसी समय से आपने सच बोलना छोड़ दिया। अगर आपको लगता है कि आप अपने धोखेबाज नेताओं - जो अब नए-नए मार्क्सवादी-लेनिनवादी बन गए हैं (हमें गृह मंत्री के तौर पर मार्क्सवादी-लेनिनवादी नक्सलियों के प्रति आपका नरम रुख याद है) और अन्य आराजकतावादिश्यों के सत्ता परिवर्तन और बांग्लादेश जैसी हिंसक इस्लामी



बगावत वाले बयानों पर पर्दा डाल सकते हैं, तो सर, फिर से सोच लें। भाजपा नेता ने आगे कहा कि लोकतंत्र में सरकार बदलने का एकमात्र वैध तरीका चुनाव ही है। उन्होंने चिदंबरम पर एक ऐसी अराजक राजनीतिक विचारधारा का बचाव करने का आरोप लगाया।

उन्होंने कहा आपको लीपापोती पर कोई यकीन नहीं कर रहा है। कोई भी समझदार भारतीय ऐसा नहीं करेगा। न अभी, न कभी। आप कभी एक अच्छे दिमाग वाले व्यक्ति हुआ करते थे। जरा उसका इस्तेमाल करें। लोकतंत्र में, और भारत में, सरकार बदलने का एकमात्र तरीका चुनाव है। अराजकतावादी और उनका बचाव करने वाले (आप), हमारे लोकतंत्र की इस अदृष्ट प्रक्रिया की जगह नहीं ले सकते। अराजकता, झूठ और लोगों को बांटने की राजनीति, एक मजबूत और विकसित भारत के उस सामूहिक संकल्प के सामने कभी नहीं टिक पाएगी, जहां सभी को समान अवसर मिलते हों। चंद्रशेखर ने कांग्रेस पर झूठे वादों और वोट-बैंक की राजनीति पर निर्भर रहने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके बजाय पार्टी को शासन, जनसेवा और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर ध्यान देना चाहिए।

स्टेल प्रमुख समाचार

शुभमन गिल की रणजी ट्रॉफी में वापसी

नईदिल्ली। भारत के टेस्ट और वनडे कप्तान शुभमन गिल की पंजाब की तरफ से रणजी ट्रॉफी में वापसी रविवार से देशभर में शुरू होने वाले इस घरेलू प्रथम श्रेणी टूर्नामेंट के दूसरे दौर का मुख्य आकर्षण होगी। गिल पंजाब के पहले दौर के मैच में नहीं खेल पाए थे। उनकी अनुपस्थिति में भारत की अंडर19 टीम के पूर्व कप्तान उदय सहारन ने टीम की कप्तानी की। इस मैच में पंजाब ने असम के खिलाफ पहली पारी में बहुत के आधार पर तीन अंक हासिल किए थे। सत्र के दूसरे दौर में पंजाब का सामना छत्तीसगढ़ से होगा।

गिल का हाल में प्रदर्शन शानदार रहा है। उन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे श्रृंखला में 334 रन बनाए। गिल ने दूसरे वनडे में 133 गेंदों पर नाबाद 223 रन बनाए और इस प्रारूप में सबसे तेज दोहरा शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। रूप बी के एक अन्य मुकाबले में कर्नाटक ऑलराउंडर श्रेयस गोपाल के नेतृत्व में अलुरु में सौराष्ट्र का सामना करेगा। इस मैच में उसे बल्लेबाज रविचंद्रन स्मरण की कमी खलेगी जिन्हें न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम में शामिल किया गया है। कर्नाटक को हालांकि चोट से उबरने वाले प्रमुख तेज गेंदबाज विठ्ठ थकावरप्पा और वैशाल विजयकुमार की वापसी से मजबूती मिलेगी। रूप बी में शिवाल पर काबिज हैदराबाद की टीम आंध्र के खिलाफ अपना अच्छा प्रदर्शन जारी रखने की कोशिश करेगी। उसने पहले मैच में त्रिपुरा को पारी और 40 रन से हराकर बोनस अंक हासिल किया था। रूप डी में मुंबई की टीम हिमाचल प्रदेश के खिलाफ उपकप्तान और सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे के बिना खेलेगी जो चोटिल हैं। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल भी इस मैच में नहीं खेल पाएंगे क्योंकि वह न्यूजीलैंड दौरे के लिए भारत ए टीम का हिस्सा है। मुंबई ने दिव्यांश सक्सेना और अंग्कृष रघुवंशी को टीम में शामिल किया है।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/

प्रमुख समाचार

मई के बाद पहली बार 110 डॉलर के पार पहुंचा ब्रेंट क्रूड

नई दिल्ली। अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में एक बार फिर तेज उछाल देखने को मिला है। ब्रेंट क्रूड का भाव मई के बाद पहली बार 110 डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गया, जबकि अमेरिकी क्रूड की कीमतों में भी करीब 4 फीसदी की तेजी दर्ज की गई। तेल की सप्लाई में जल्द राहत मिलने की उम्मीद कमजोर पड़ने और कई क्षेत्रों में बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव ने ऊर्जा बाजार की चिंता बढ़ा दी है। हूती विद्रोहियों के सऊदी अरब के तेल टिकानों पर हमलों और रूस-यूक्रेन के बीच ऊर्जा संयंत्रों तथा रिफाइनरियों को निशाना बनाए जाने से वैश्विक तेल आपूर्ति परभावित होने की आशंका है। इससे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ा है। कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के पीछे सबसे बड़ी वजह सप्लाई को लेकर बढ़ती चिंताएं हैं।

चीनी 60 रुपए के पार दूध 30 प्रतिशत महंगा

नईदिल्ली। त्योहारों का मौसम शुरू हो गया है और बाजारों में रौनक भी बढ़ गई है। कोई खुशी का मौका हो या उत्सव मिठाइयों हर किसी की पंसद होती हैं। दक्षिण भारत के सामान्य लड्डू से लेकर उत्तर भारत की मावे वाली बर्फी और कोलकाता के मशहूर संदेश से लेकर ओडिशा के छेना पोढ़ा व रसगुल्ले तक, देश में लगभग सभी मिठाइयों की कीमतें पिछले साल के मुकाबले इस त्योहारो मौसम में औसतन 10 से 15 फीसदी बढ़ गई हैं। चितरंजन मिश्रात्र भंडार के नितार्इ चंद्र घोष ने कहा, ‘3-4 महीने पहले चीनी का भाव 44 रुपये प्रति किलोग्राम था। अब यह 60 रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गया है।’ वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर महंगा होने के कारण मिठाई निर्माताओं ने मिठाइयों की खुदरा कीमतों में 25 से 30 रुपये प्रति किलोग्राम की वृद्धि की है।

आईडीबीआई बैंक बेचने पर हुआ सवाल, तो सरकार ने खोली फाइल

नईदिल्ली। आईडीबीआई बैंक में अपनी हिस्सेदारी बेचने के सरकार के फैसले पर वित्त मंत्रालय ने शनिवार को सफाई दी। मंत्रालय का कहना है कि बैंक को बेचने का फैसला आचानक नहीं लिया गया है। इसकी तैयारी साल 2003 से चल रही नीतिगत प्रक्रिया का हिस्सा है। मंत्रालय के मुताबिक, संसद में बने पुराने कानून, दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले और सरकार के कई बजट भाषणों में भी इस प्रक्रिया के संकेत मिलते रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आईडीबीआई बैंक की 60.72 फीसदी हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स को बेचने की मंजूरी दी है। इस सौदे की कीमत करीब 53,000 करोड़ रुपये है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, साल 2003 में जब संसद में आईडीबीआई बैंक से जुड़ा कानून वापस लेने के विधेयक पर चर्चा हो रही थी, तब सरकार की हिस्सेदारी घटाने पर रोक लगाने के लिए संशोधन का प्रस्ताव रखा गया था।

लाइसेंस पर एलन मस्क-मुकेश अंबानी आमने-सामने!

नईदिल्ली। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू करने को लेकर ईलॉन मस्क की कंपनी स्टारलैंक और रिलायंस इंडस्ट्रीज के बीच बयानबाजी तेज हो गई है। स्टारलैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह भारत में हाई-स्पीड इंटरनेट सेवा शुरू करने के लिए तैयार है। कंपनी के मुताबिक, वह पिछले पांच साल से ज्यादा समय से भारत के नियामकों, टेलीकॉम कंपनियों और उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इस दौरान उसने देश में अपने नेटवर्क, गेटवे और दूसरी जरूरी सुविधाएं भी तैयार की हैं। कंपनी का कहना है कि ये सभी तैयारियां जरूरी सरकारी मंजूरियों के साथ की गई हैं। स्टारलैंक ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना बयान जारी करते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज के बयान को भी ठीग किया।

भू-राजनीतिक जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई को मौद्रिक नीति में बदलाव की जरूरत

टी टी राम मोहन

इस वर्ष मई में रुपया कमजोर होते हुए डॉलर के मुकाबले 96 का स्तर पार कर गया। इसके बाद जून में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने विदेशी निवेश बढ़ाने के लिए मुद्राओं की रियायती अदला-बदली (स्वैप) सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कई उपायों का एलान किया। इनमें खासकर विदेशी मुद्रा अनिवासी (बैंक) जमा यानी एफसीएनआर (बी) शामिल थी। तब उम्मीद की गई थी कि इन उपायों से लगभग 50 अरब डॉलर निवेश आएगा और रुपया पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी।

इस स्तंभ के लेखक ने उस समय तर्क दिया था कि तेल की कीमतों और विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) की तरफ से बिकवाली की आशंका देखते हुए आरबीआई की योजनाओं के तहत आने वाली रकम नाकाफी साबित होगी। नीतिगत

दर में बढ़ोतरी तय है और वही हुआ। मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने 7 अक्टूबर को रीपो दर 25 आधार अंक बढ़ाने का निर्णय लिया।

आरबीआई के खास उपायों के तहत कुल 143 अरब डॉलर का भारी-भरकम निवेश आया। मगर इससे रुपये की सेहत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा है और यह डॉलर के मुकाबले 96 के इर्द-गिर्द काउंटाबर कर रहा है। दो महीने के अंतराल के बाद सितंबर में एफआईआई ने फिर बिकवाली शुरू कर दी और कुल 6 अरब डॉलर रकम काफ़ूर हो गई।

जून के बाद से आर्थिक माहौल में दो अहम बदलाव आए हैं। कच्चे तेल की कीमत 85-90 डॉलर से बढ़कर अब 100 डॉलर से ऊपर चली गई है। यह तेल की वायदा कीमत है। कच्चे तेल की वायदा बाजार कीमत भारत के लिए यहां तक पहुंचने की लागत नहीं



दर्शाती है। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार का कहना है कि वर्तमान में भारत के तेल आयात बास्केट की कीमत 114 डॉलर है। यह वित्त वर्ष 2026 में 71 डॉलर की औसत कीमत के मुकाबले 61 फीसदी की बढ़ोतरी है। तेल के दाम उस स्तर पर पहुंच गए हैं जो हमारी सुविधाजनक दायरे से काफी ऊपर हैं।

दूसरा कारण पिछले महीने अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दर में 25 आधार अंक की बढ़ोतरी का निर्णय है। माना जा रहा है कि फेडरल रिजर्व दरें और बढ़ा सकता है क्योंकि अमेरिका में

मुद्रास्फीति निर्धारित सीमा या लक्ष्य से ऊपर बनी हुई है।

अमेरिकी सरकारी बॉन्ड (ट्रेजरी) पर यील्ड में किसी भी बढ़ोतरी का भारत पर दो तरह से असर पड़ता है। पहला, इससे आम तौर पर भारत जैसे उभरते बाजारों से धन बाहर निकल जाता है जिससे रुपया कमजोर होता है। दूसरा, इससे अमेरिका और भारत में 10 वर्ष की अवधि के बॉन्ड पर मिलने वाले यील्ड के बीच का अंतर कम हो जाता है। 195 आधार अंक पर 10 वर्ष की अवधि के सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाली यील्ड का अंतर पिछले पांच वर्षों में सबसे कम है। यह भी रुपये के मूल्य ह्रास का एक बड़ा कारण रहा है। आरबीआई रुपये को किसी खास स्तर पर रोके नहीं रखना चाहता। मगर उसे रुपये की कीमत में आई गिरावट थामने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ता क्योंकि ऐसा नहीं करने पर देश में मुद्रास्फीति बढ़ सकती है।

जून में घोषित उपाय रुपये को थामने में कामयाब नहीं हो पाए। इसके बजाय, वित्तीय तंत्र में अतिरिक्त नकदी आ गई जिनमें लगभग आधी आरबीआई ने वापस खींच ली है। वित्तीय तंत्र में अतिरिक्त नकदी होने से ब्याज दरों में बढ़ोतरी का असर दिखना और मुश्किल हो जाता है। इस तरह, जून और अगस्त में ब्याज दरें नहीं बढ़ाने से आरबीआई को अब कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें तेल की ऊंची कीमतें, अतिरिक्त नकदी, अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर यील्ड में बढ़ोतरी, अमेरिका और भारत में दीर्घ अवधि की यील्ड के बीच कम अंतर और एफआईआई की तरफ से लगातार बिकवाली शामिल हैं। अगर नीतिगत दर पहले ही बढ़ा दी जाती तो आरबीआई का काम आसान हो जाता। इससे विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर बेचकर दखल देने की जरूरत भी कम हो सकती थी।

‘ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा’

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने तीन गांवों में 1.55 करोड़ रुपए के गौरव पथ निर्माण का किया भूमिपूजन

कवर्धा। नवरात्रि के पावन अवसर पर उप मुख्यमंत्री कवर्धा विधायक श्री विजय शर्मा ने कबीरधाम जिले के ग्राम सारंगपुर कला, कारेसरा और मड़मड़ में कुल 1 करोड़ 55 लाख 67 हजार रुपए की लागत से गौरव पथ निर्माण का भूमिपूजन कर ग्रामीणों को विकास की सौगात दी। इसमें ग्राम सारंगपुर कला में 47.85 लाख रुपए, कारेसरा में 59.63 लाख रुपए और मड़मड़ में 48.19 लाख रुपए की लागत से गौरव पथ का निर्माण किया जाएगा। इन निर्माण कार्यों से तीनों गांवों में सड़क सुविधा बेहतर होगी और ग्रामीणों को आवागमन में सहूलियत मिलेगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने मां दुर्गा की पूजा-अर्चना कर प्रदेश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा भी की।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने अधिकारियों को गौरव पथ निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और टिकाऊपन का विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़कें ऐसी बननी चाहिए, जो लंबे समय तक चलें और ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की सुविधा दें। निर्माण कार्यों में लापरवाही किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ग्राम बंदोरा की सड़क का उदाहरण देते हुए बताया कि सड़क की खराब स्थिति की शिकायत मिलने पर उन्होंने तत्काल उसे उखाड़कर दोबारा बनाने के निर्देश दिए थे। अगले ही दिन सड़क उखाड़ने की कार्रवाई शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि गांव की सड़कों का उपयोग ग्रामीण ही करते हैं, इसलिए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर नजर रखने और किसी भी कमी की जानकारी देने में स्थानीय लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। इस अवसर पर जिला



पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, जिला पंचायत सदस्य मनीराम साहू, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष श्री विदेशीराम धुर्वे, जनपद अध्यक्ष श्री रामकिंकर वर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित थे।

उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र

मोदी के नेतृत्व और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के मार्गदर्शन में नक्सलवाद के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें सफलता मिली है। बस्तर में पेड़ों की कटाई और बड़ी खनन परियोजनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं पर उन्होंने कहा कि इन विषयों पर लोगों के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है।

‘ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर सुनीं समस्याएं’

कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री श्री विजय शर्मा ने अपने सहज अंदाज में ग्रामीणों के बीच जमीन पर बैठकर उनसे सीधा संवाद किया। उन्होंने लोगों की समस्याएं और मांगें सुनीं तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनके निराकरण के लिए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने ग्राम सारंगपुर कला में 5.20 लाख रुपये की लागत से सीसी रोड निर्माण की घोषणा की। ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी जरूरतों को सुनने और संबंधित अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश देने से जनसमस्याओं के समाधान पर जोर दिया गया। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि नई संरचना के गठन के बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 12 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को आवास का लाभ दिलाने के लिए सर्वे सूची के अनुसार आगे की प्रक्रिया जारी रहेगी।

नगरीय निकाय चुनाव में प्रचंड जीत हमारा लक्ष्य : कर्मवीर



रायपुर। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में शनिवार को आगामी नगरीय निकाय चुनाव को लेकर एक आवश्यक बैठक संपन्न हुई। बैठक में चुनावी रणनीति, संगठनात्मक तैयारियों और बृथ स्तर तक कार्यकर्ताओं की सक्रियता को लेकर विस्तार से रणनीतिक चर्चा हुई।

बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव में भाजपा का लक्ष्य सभी नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों में जीत हासिल करना है। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को घर-घर तक पहुंचाना और प्रत्येक बृथ को मजबूत करना ही हमारी जीत का आधार होगा। हमारा

लक्ष्य केवल नगरीय निकाय चुनाव ही नहीं, बल्कि यह चुनाव आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी भी है। नगरीय निकाय चुनाव के साथ हमें विधानसभा में भी प्रचंड जीत हासिल करनी है। भाजपा प्रदेश महामंत्री अखिलेश सोनी ने कहा कि भाजपा पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी और प्रदेश के सभी नगरीय निकायों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने पिछले एक वर्ष में नगरीय क्षेत्रों के विकास के लिए अभूतपूर्व कार्य किए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के शहर स्वच्छ, सुंदर और विकसित हो रहे हैं। जनता का विश्वास भाजपा के साथ है।

धमतरी जिला के मोंगरागहन में मेगा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

धमतरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनसेवा के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचालित ‘सेवा संकल्प अभियान’ के अंतर्गत ग्राम मोंगरागहन में एक दिवसीय विशाल निःशुल्क मेगा स्वास्थ्य शिविर का सफल आयोजन किया गया। कलेक्टर धमतरी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम प्रबंधक के मार्गदर्शन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुजरा द्वारा आयोजित इस शिविर में क्षेत्र के 641 ग्रामीणों ने अपना पंजीयन काराकर विशेषज्ञ डॉक्टरों से निःशुल्क जांच, परामर्श, उपचार एवं दवाओं का लाभ उठाया। शिविर का भव्य शुभारंभ



जिला पंचायत अध्यक्ष धमतरी द्वारा किया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत स्वास्थ्य सभापति, जनपद सदस्य, मोंगरागहन और कोडेगांव सरपंच, अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष और गंगरेल महामंत्री सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

समारोह को संबोधित करते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष धमतरी ने कहा कि स्वस्थ समाज के

केंद्रीय उप सचिव ने शिक्षा एवं आजीविका संवर्धन कार्यों का किया निरीक्षण

नारायणपुर। भारत सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय के उप सचिव प्रशांत एमएस. ने कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन के साथ शनिवार को नारायणपुर जिले के भ्रमण के दौरान शिक्षा एवं कृषि क्षेत्र में संचालित गतिविधियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्कूल केइन्ता अभियान के अंतर्गत संचालित वैकल्पिक शाला मुसेर में बच्चों की शैक्षणिक गतिविधियों का अवलोकन किया तथा गुमियाबेड़ा में पौधरोपण एवं बागवानी के माध्यम से आजीविका संवर्धन के प्रयासों की जानकारी ली भ्रमण के दौरान केंद्रीय उप सचिव प्रशांत एम.एस. ने स्कूल केइन्ता अभियान का अंतर्गत संचालित वैकल्पिक



शाला मुसेर का निरीक्षण कर शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया, बच्चों की सहभागिता तथा विद्यालय में संचालित गतिविधियों की जानकारी प्राप्त की। स्कूल केइन्ता अभियान का उद्देश्य दूरस्थ एवं पहुंचविहीन क्षेत्रों में शिक्षा से वंचित बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना और उन्हें सीखने के अवसर उपलब्ध कराना है।

ग्रामीण विकास में पंच-सरपंचों की सक्रिय भागीदारी जरूरी : वन मंत्री केदार

नारायणपुर। सेवा संकल्प अभियान के अंतिम दिवस नारायणपुर में आयोजित जिला स्तरीय पंच-सरपंच प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण कार्यक्रम में ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जनभागीदारी बढ़ाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वन मंत्री श्री केदार कश्यप ने कहा कि गांवों के विकास और शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में पंच-सरपंचों की महत्वपूर्ण भूमिका है। जनप्रतिनिधि ग्रामीणों की जरूरतों को समझकर विकास की प्राथमिकताएं तय करें और योजनाओं के क्रियान्वयन में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करें।



नारायणपुर के सिनेमा ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में वन मंत्री श्री कश्यप ने विवकसित भारत की राम जी योजना की सफलता के लिए पंचायत प्रतिनिधियों से सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि पंच-सरपंच गांवों में जाकर लोगों को योजनाओं के उद्देश्य और लाभ की जानकारी दें। पात्र

हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर काम करें। उन्होंने कहा कि जनविश्वास और जनभागीदारी से ही ग्रामीण विकास की योजनाओं के बेहतर परिणाम सामने आएंगे।

उन्होंने कहा कि स्कूल भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, छात्रावास, सामुदायिक भवन, बालिका शौचालय, मुक्तिधाम, सड़क, पुल-पुलिया और महतारी सदन जैसे जनोपयोगी कार्यों का समय सीमा में पूर्णता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि पंचायत प्रतिनिधि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की नियमित निगरानी करें, ताकि ग्रामीणों को जल्द बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

देवेंद्र नगर व बूढ़ापारा केंद्र की महिलाओं ने निकाली दुर्गा दौड़



रायपुर। महाराष्ट्र मंडल की ओर से प्रतिदिन निकाली जाने वाली दुर्गा दौड़ की कड़ी में देवेंद्र नगर और बूढ़ापारा महिला केंद्र की महिलाओं ने क्रमशः गुरुवार व शुक्रवार को दुर्गा दौड़ का आयोजन किया। बूढ़ापारा केंद्र की महिलाओं ने मंडल के छत्रपति शिवाजी महाराज कार्यक्रम आयोजन समिति के पुरुष प्रमुख गणेशा जाधव पाटिल, साहित्य समिति प्रमुख अभय भागवतकर और वैभव बर्वे की उपस्थिति में दुर्गा दौड़ का आयोजन किया। वहीं देवेंद्र नगर महिला केंद्र ने स्थानीय हनुमान मंदिर से समीपस्थ दुर्गा पंडाल कर दुर्गा दौड़ निकाली। देवेंद्र नगर केंद्र की संयोजिका नम्रता गान्गाने ने बताया कि दुर्गा दौड़ में सभी महिलाएं भगवा ध्वज लेकर पहुंची थीं। माता के सोलह श्रृंगार के बाद उनकी आरती उतार कर प्रदेश, राष्ट्र की सुख-समृद्धि की प्रार्थना की गई। दौड़ में केंद्र की सह संयोजिका हर्षदा भारवे, पद्मजा लाड के अलावा मीना लोणकर, श्वेता सायंकार, शीतल रणदीवे, संगीता चक्रवर्त, साक्षी ठोडे, चित्रा खुंडे, सविता मोतलंग, स्वाती जगताप शामिल हुए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन हेल्पलेस हो गयी है : कांग्रेस

रायपुर। कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा शुरू किये गए मुख्यमंत्री हेल्पलाइन को केवल राजनैतिक नौटंकी बताया है। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में बैठे लोगों द्वारा मिलने वाली शिकायतों को केवल समस्याओं को संबंधित विभाग में रेफर कर देने को समाधान बता कर



है उसे जनता की समस्याओं के निराकरण से कोई मतलब नहीं है। मुख्यमंत्री निवास में भी हर गुरुवार को जनता से मिलने का कार्यक्रम शुरू हुआ था, ढाई साल में आधा दर्जन गुरुवार को भी मुख्यमंत्री लोगों से नहीं मिले। भाजपा सरकार ने कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में मंत्रियों को नियमित बैठने की घोषणा किया वह भी बंद हो गया। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन भी बहुत जल्दी उबाऊ कॉल सेंटर में तब्दील होगा फिर बंद हो जायेगा।

प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि सरकार की ओर से 16 अक्टूबर 2026 को प्रकाशित जानकारी के अनुसार, 9 जून से 15 अक्टूबर 2026 के बीच

आबकारी विभाग के तत्कालीन उपायुक्त श्रीवास्तव निलंबित

रायपुर। राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण एवं एंटी करप्शन ब्यूरो में दर्ज अपराध क्रमांक 04/2024, धारा 7, 7-क, 8, 12, 13 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (यथासंशोधित 2018) एवं 420, 467, 468, 471, 120बी, 201, 109 भा. द. वि. के प्रकरण में लोक सेवक आरोपी आशीष श्रीवास्तव, तत्कालीन उपायुक्त आबकारी, रायपुर, छत्तीसगढ़ के विरुद्ध विवेचना उपरंत प्रथम दृष्टया सिद्ध पाए जाने से पूरक अभियोग पत्र क्रमांक 03(1)/2024 दिनांक 13.10.2026 तैयार कर माननीय विशेष न्यायालय (भ्र.नि.अधि.), रायपुर में दिनांक 14.10.2026 को प्रस्तुत किया गया है।

राज्य शासन, एतदद्वारा, माननीय न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के फलस्वरूप, छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (ख) के परन्तुक में निहित प्रावधान उपरंत प्रथम दृष्टया अपर आयुक्त आबकारी, कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़ को माननीय न्यायालय में चालान प्रस्तुति दिनांक 14.10.2026 से निलंबित कर दिया है निलंबन अवधि में आशीष श्रीवास्तव का मुख्यालय कार्यालय आबकारी आयुक्त, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर में निर्धारित किया जाता है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी। उक्त आदेश वाणिज्यिकर (आबकारी) विभाग के विशेष सचिव देवेन्द्र सिंह भारद्वाज के हस्ताक्षर से जारी हुआ।

बुराइयों के रावण का ज्ञान के राम से होगा अंत



रायपुर। महाराष्ट्र मंडल के संत ज्ञानेश्वर विद्यालय में नवमी - विजयादशमी की छुट्टी लगने से पहले शुक्रवार को मार्निंग असेंबली में दशहरा उत्सव मनाया गया। इस दौरान बच्चों ने अपनी सुंदर नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से बताया कि समाज में फैली हुई बुराइयों के दशानन को ज्ञान रूपी श्रीराम से नष्ट किया जा सकता है। पूरे कार्यक्रम का मार्गदर्शन ग्रीन हाउस इंजार्ज शिक्षिका रेणुका शुक्ला ने किया। शिक्षिका अपर्णा आठले ने बताया कि दशहरे से पहले ही स्कूल के बच्चों ने इस त्योहार को धूमधाम से मनाया। मार्निंग असेंबली का संचालन पांचवीं की दिव्या ने किया। वहीं लव पाठक ने छात्रों को प्रतिज्ञा दिलाई। इस अवसर पर पलक साहू, आरुषि सेन, गुंजिता साहू, अभिज्ञा शुक्ला, डी जयराम, मुतुल बाघ और होसी सैनेवानी ने नाट्य प्रस्तुति के माध्यम से समाज में फैली कुरीतियों को दशार्ति हटाने के माध्यम से उन्हें नष्ट करने का मंचन किया।

बस्तर दशहरा में बेल नेवता पूजा के बाद आज बेल पूजा

जगदलपुर। बस्तर दशहरा में फूल रथ की पांचवी परिक्रमा के बाद आज रात्रि में बेल नेवता (नेमता) पूजा विधान संपन्न की जायेगी। बेल नेवता विधान के तहत शहर सीमा से लगे ग्राम सरगीपाल जाकर बेल वृक्ष में जुड़वां बेल फल की पूजा की जाती है। पूजा-अर्चना के पश्चात् जुड़वां बेल फल की शाखा में नारियल और सुपारी के साथ लाल कपड़ा बांधकर दशहरा का निमंत्रण दिया जाता है, स्थानीय बोली में निमंत्रण को नेवता कहा जाता है। राज परिवार के सदस्य जुड़वा बेल को तोड़ने के एक दिन पूर्व यहां आकर विधिवत् पूजा-पाठ के बाद इन जुड़वां बेल फल पर लाल कपड़ा बांधकर बेल नेवता पूजा विधान करने के बाद रियासत कालीन परंपरासुसार रविवार 18 अक्टूबर को सुबह 11 बजे पारंपरिक बेल पूजा विधान संपन्न किया जाएगा। जगदलपुर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित ग्राम सरगीपाल में एक प्राचीन बेल वृक्ष के साथ यह सदियों पुरानी रस्म पूरी विधि-विधान, श्रद्धा और उल्लास के साथ निभाई जाएगी। ग्रामीण इन फलों की विदाई को बेटी की विदाई जैसा मानते हैं। वे इस मौके पर जमकर हल्दी खेलते हैं। इन युग्म बेल में देवी दुर्गा का और महालक्ष्मी का रूप माना जाता है, इन युग्म फलों को राजगुरु और पुजारी युग्म बेल को दत्तेश्वरी मंदिर में लाकर स्थापित किया जाता है। इस वृक्ष की जड़ों में गिरिजा, तना में माहेश्वरी, शाखाओं में दाक्षायनी अर्थात् राजा दक्ष कीपुत्री, पत्तियों में पार्वती, फूलों में गौरी, फलों में कात्यायनी का वास होता है।

दुर्ग जिला न्यायालय में ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ पर विधिक संगोष्ठी का आयोजित

तकनीक से सुगम न्याय, विधि से सुनिश्चित निष्पक्षता

दुर्ग। न्याय की राह में दूरियाँ कम हो रही हैं और तकनीक न्यायिक प्रक्रिया को नए आयाम दे रही है। अब ऑडियो-वीडियो माध्यमों से साक्ष्य दर्ज करने से लेकर डिजिटल साक्ष्यों के महत्व को समझने तक, न्याय व्यवस्था में तकनीक की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है। ऐसे में तकनीक का उपयोग केवल सुविधाजनक ही नहीं, बल्कि विधिस्मत्त, निष्पक्ष और विश्वसनीय होना भी आवश्यक है।

इसी दृष्टिकोण को केंद्र में रखते हुए जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग में 16 अक्टूबर को ऑडियो-वीडियो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से न्यायिक कार्यवाही एवं न्याय श्रुति नियम, 2025 का विधिक एवं व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य विषय पर विधिक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में न्यायिक कार्यवाही के आधुनिक स्वरूप,



साक्ष्य की प्रक्रिया और तकनीकी साधनों के विधिस्मत्त उपयोग पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के साथ ई-साक्ष्य एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी भी आयोजित की गई, जिसने आयोजन को व्यावहारिक और ज्ञानवर्धक स्वरूप प्रदान किया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री के. विनोद कुजूर तथा प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दुर्ग श्रीमती सुमन एक्का की गरिमायमयी उपस्थिति में आयोजित संगोष्ठी में

द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री प्रशांत पारार ने ‘न्याय श्रुति नियम, 2025’ के प्रमुख प्रावधानों और उनके व्यावहारिक क्रियान्वयन पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम का अधिभाषण प्रथम व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ श्रेणी, दुर्ग कु. दीपांशी जैन द्वारा प्रस्तुत किया गया। संगोष्ठी में इस बात पर बल दिया गया कि आधुनिक तकनीक न्यायिक कार्यवाही को अधिक सुगम और समयबद्ध बनाने में सहायक हो सकती है, लेकिन इसका प्रभावी उपयोग तभी

संभव है, जब विधिक प्रावधानों का पालन करते हुए साक्ष्य की विश्वसनीयता और न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता सुनिश्चित की जाए। संगोष्ठी का एक महत्वपूर्ण आकर्षण प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, दुर्ग द्वारा आयोजित ई-साक्ष्य की प्रक्रिया एवं डिजिटल साक्ष्यों से संबंधित प्रदर्शनी रही। प्रदर्शनी का उद्देश्य डिजिटल साक्ष्यों की प्रक्रिया, उनके महत्व और न्यायिक कार्यवाही में उनकी प्रासंगिकता के प्रति समझ विकसित करना था। इस पहल ने संगोष्ठी की विषयवस्तु को व्यावहारिक आयाम प्रदान किया। जहाँ संगोष्ठी में नियमों और प्रक्रियाओं की विधिक जानकारी को एक अलग और सहज स्वरूप में प्रस्तुत किया गया।

कमीशन राज में बह गया डामर, सड़कों के गड्डों में हिचकोले खा रही राज्य की जनता : दीपक बैज

रायपुर। लोक निर्माण विभाग की सुस्त कार्यप्रणाली, भ्रष्टाचार, और प्रदेश भर में सड़कों की बदहाली को लेकर सवाल उठाते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की सड़कों की हालत आज किसी से छिपी नहीं है। प्रदेश की राजधानी से लेकर दूर-दराज के इलाकों तक सड़कें पूरी तरह गायब हो चुकी हैं और सिर्फ जानलेवा गड्डे बचे हैं। लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) विकास का नहीं, बल्कि डामर घोटाले और टेंडर कमीशनखोरी का केंद्र बन चुका है। विष्णुदेव साय की सुशासन की बातें सिर्फ विज्ञापनों में हैं, धरातल पर जनता धूल फांकने और हादसों



में जान गंवाने को मजबूर है। कांग्रेस पार्टी जनता के इस दर्द को खामोशी से नहीं देखेगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि भाजपा सरकार विकास के बड़े-बड़े दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि राजधानी रायपुर से लेकर बस्तर और सरगुजा तक राज्य की

मुख्य सड़कें और राजमार्ग गड्डों में तब्दील हो चुके हैं। निर्माण के नाम पर सिर्फ टेंडर निकाले जा रहे हैं, लेकिन धरातल पर काम पूरी तरह ठप है। पीडब्ल्यूडी विभाग में कमीशनखोरी और सिंडिकेट राज हावी हो चुका है। घंटियां फिस्म के डामर का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो पहली बारिश भी नहीं झेल पाता। पर्सदीया ठेकेदारों की रेवड़ियों की तरह टेंडर बांटे जा रहे हैं, जबकि कार्य की गुणवत्ता जांचने वाला कोई नहीं है। बजट का एक बड़ा हिस्सा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। धूल, गड्डों और आए दिन हो रहे भीषण सड़क हादसों के कारण जनता और राहगीर अपनी जान गंवा रहे हैं।